राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 27 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-205 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

नेपाल में जलप्रलय 16 की मौत, 105 भारतीय लापता, व्यापक बचाव अभियान जारी

काठमांडू।

नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लेन्दे खोला (भोटेकोशी नदी) में उफान से टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आपदा में अब तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 105 भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबर है। स्थिति की गंभीरता को देखकर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है, जिसमें 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बाढ़ के तेज बहाव में कई वाहन और अन्य सामान बह गए हैं। कुल 13 जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनके बांध, विद्युतगृह, पहुंच मार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची है। काठमांडू ट्रैफिक पुलिस ने एहतियात के तौर पर काठमांडू से रसुवा, नुवाकोट, चितवन और धादिङ जाने वाले वाहनों की आवाजाही को रोक दिया है। बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने बताया कि बुसी और तुसु जैसे प्रभावित इलाकों से 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। कुल 15 हेलीकॉप्टरों में से 7 नेपाली सेना के और 8 अन्य एजेंसियों के हैं, जो बचाव अभियान में लगे हैं। घायलों के उपचार के लिए मछली ट्रेनिंग कैंप में एक मेडिकल सेंटर स्थापित किया गया है, और प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल व बचाव टीमें तैनात की गई हैं। स्थानीय अधिकारियों और नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के खतरे को लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि सेना और मेडिकल टीमें फिलहाल बचाव कार्य पर केंद्रित हैं, और मृतकों व घायलों की सटीक संख्या का आकलन

अभी जारी है। व्यापक नुकसान का विस्तृत आकलन स्थलीय निरीक्षण के बाद ही किया जा सकेगा।

इस बीच, नेपाल में आई इस बाढ़ के मद्देनजर बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

झारखंड में लो-प्रेशर सिस्टम सक्रिय, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

-मानसून टर्फ और हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बारिश का माहौल कर रहे मजबूत

नई दिल्ली।

झारखंड में कई इलाकों में बारिश से राहत की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने फिर करवट ले ली है। झारखंड और आसपास के इलाकों में बने नए लो-प्रेशर के क्षेत्र में सिस्टम सक्रिय हो गया है। आईएमडी ने 23 राज्यों के लिए बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं यानी अगले कुछ दिन सफर करने वालों से लेकर किसानों और समुद्र में जाने वाले मछुआरों तक सभी को मौसम पर नजर रखनी होगी। खासकर उन इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है जहां पहले से जलभराव या भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस मौसम बदलाव की सबसे बड़ी वजह झारखंड और उसके आसपास बना लो-प्रेशर का क्षेत्र है। यह सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने वाला है। इसका असर झारखंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक दिखाई देगा। इसके अलावा मानसून टर्फ और ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बारिश का माहौल मजबूत कर रहे हैं। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए लोगों को खुले इलाकों, पेड़ों और कमजोर कंस्ट्रक्शन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। तेज बारिश में सड़क पर विजिबिलिटी भी घट सकती है। ऐसे में बिना जरूरत यात्रा करना परेशानी बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 26 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों समेत 23 राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है। तेज हवा से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का खतरा भी रहता है। इसलिए मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित जगह पर रहना ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली-एनसीआर में 26 अगस्त को मौसम फिर करवट ले सकता है। आईएमडी ने दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। 26 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। कुछ स्थानों पर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बिहार में मौसम का असर और ज्यादा तेज नजर आ सकता है। यहां हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले में खड़े लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पेड़ों और बिजली के तारों से दूरी बनाना जरूरी है। राजस्थान में भी मानसून का असर कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं में खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की जरूरत होगी।

टीएमसी की बड़ी कामयाबी- 20 बागी सांसदों की अयोग्यता की मांग तेज

कोलकाता ।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद सागरिका घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फ़ैसले का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने दल-बदल कानून के उल्लंघन के आरोप में 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। टीएमसी सांसद घोष ने एक बड़ी कामयाबी करार देकर कहा कि आखिरकार दो महीने बाद स्पीकर कार्यालय ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ये वहां सांसद हैं जो एक खास चुनाव चिह्न पर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इन सांसदों पर गद्दार होने का आरोप लगाकर कहा कि ये जनता के जनादेश के साथ धोखा कर रहे हैं। घोष ने संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला देकर इन्हें तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग की।

हनुमान मंदिर से दानपेटी चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2,890 रुपए बरामद

मेरठ।

यूपी में मेरठ में हनुमान मंदिर से दानपेटी चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई खाली दानपेटी और 2,890 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई है, जो मुण्डाली थाना क्षेत्र के जिसौरी गांव का रहने वाला है।पुलिस के मुताबिक 28 जुलाई की रात आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मुण्डाली गांव स्थित हनुमान मंदिर से दानपेटी चोरी की थी। दोनों ने दानपेटिका में रखी रकम आपस में बांट ली और खाली दानपेटी को खेतों में फेंक दिया था। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की गई दानपेटी और 2,890 रुपए बरामद किए गए।

शिवराज का पलटवार-कांग्रेस ने ही बिगाड़ा एक देश,एक चुनाव का सिस्टम

नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम द्वारा एक देश, एक चुनाव के विरोध पर तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने तर्क दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले एक साथ ही होते थे, लेकिन तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीकों से व्यवस्था को बिगाड़ दिया। इससे पहले, चिदंबरम ने एक देश, एक चुनाव को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताकर कहा था कि इस 2029 में लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष अपनी बात रखी थी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1970 के दशक में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराकर इस सुचारु व्यवस्था को खत्म किया गया था। उन्होंने कहा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव पहले एक साथ ही होते थे, ऐसा 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुआ था। बाद में, कांग्रेस पार्टी ने असंवैधानिक साजिशें रचकर इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। उन्होंने चिदंबरम के किस अंतरात्मा की बात वाले बयान पर भी सवाल उठाया।

एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन कर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लॉ कमीशन ने 1983 और 2018 में, साथ ही पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने भी एक साथ चुनाव कराने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि जब इन प्रतिष्ठित निकायों ने जरूरी बताया है, तब यह असंवैधानिक कैसे हो गया? यह प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर अन्य चुनाव कराने का सुझाव देता है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि देश भर में बार-बार होने वाले चुनावों से चुने हुए नेता विकास कार्यों पर पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं।

उन्होंने दावा किया कि इससे सरकार और राजनीतिक दलों का खर्च भी बढ़ता है, और शिक्षक, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी जैसे जनसेवक चुनाव तैयारियों में

ही उलझे रहते हैं, जबकि उन्हें जनसेवा, कल्याण और विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि एक देश, एक चुनाव राष्ट्रीय हित में है और मोटे तौर पर जनता के बीच भी इस पर व्यापक सहमति है।

गिरिराज का ओवैसी को पलटवार,संविधान के हिसाब से रहना होगा भारत में

नई दिल्ली ।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम और सांसद प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कड़ा जवाब देकर कहा है कि जो कोई भी भारत में रहना चाहता है, उस देश के संविधान का सख्ती से पालन करना होगा।

ओवैसी ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी, जिस केंद्रीय मंत्री सिंह ने न्यायपालिका का अनादर बताया।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने ओवैसी के दावों पर सवाल उठाया कि अदालती फैसला समुदाय के मामलों में दखल है। उन्होंने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि ओवैसी खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे संविधान का सम्मान करते हैं या उसके खिलाफ काम करते हैं? जब अदालतें उनकी पसंद के फैसले सुनाती हैं, तब वे स्वीकार करते हैं, लेकिन असहमत होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का विरोध क्यों करते हैं? केंद्रीय मंत्री ने ओवैसी को चुनौती देकर कहा कि अगर वे सिर्फ शरिया कानून को ही प्राथमिकता देते हैं, तब देश भर के मुसलमानों को चोरी के मामलों में हाथ काटने के शरिया प्रावधान को लागू करना चाहिए।

जबलपुर में युवक 37 लाख की ऑनलाइन ठगी का शिकार

होटल रेटिंग के नाम पर वर्क फ्रॉम होम का झांसा, कई किस्तों में ट्रांसफर कराए लाखों रुपए

जबलपुर।

अधारताल थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय युवक से होटल रेटिंग के नाम पर 37 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। टेलीग्राम और एक ऐप के जरिए जालसाजों ने युवक को घर बैठे कमाई का झांसा दिया। शुरुआत में मुनाफा देकर भरोसा जीतने के बाद उससे अलग-अलग माध्यमों से लाखों रुपए ट्रांसफर कराए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधारताल थाना क्षेत्र के जागृति नगर अमखेरा निवासी 29 वर्षीय विक्रांत साहू ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। आरोप है कि अज्ञात जालसाजों ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम और होटल रेटिंग के जरिए कमाई का झांसा देकर कुल 37,61,566 रुपए ट्रांसफर करा लिए। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को केवल 61,143 रुपए वापस मिले।

होटल रेटिंग के नाम पर शुरू हुआ संपक.....

पीड़ित के मुताबिक, 8 जनवरी 2025 को टेलीग्राम पर अदिति रियांश नाम से मैसेज आया। इसमें सीक्रेट एस्केप्स के माध्यम से होटलों को रेटिंग देकर मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। शुरुआत में रेटिंग के बदले 1,024 रुपए दिए गए। इसके बाद 10,000 रुपए के डिपॉजिट पर 17,546 रुपए और 20,960 रुपए के निवेश पर 42,573 रुपए वापस किए गए।

इससे पीड़ित को जालसाजों पर भरोसा हो गया और वह लगातार बड़ी रकम निवेश करता चला

गया।

अलग-अलग माध्यमों से ट्रांसफर कराए रुपए.....

11 से 15 जनवरी 2025 के बीच पीड़ित ने एनईएफटी, आरटीजीएस और फोनपे के माध्यम से कई किस्तों में रकम ट्रांसफर की। इसके अलावा पत्नी, साथी और परिचित के खातों से भी रकम भेजी गई। पीड़ित के अनुसार, कुछ रकम बैंक शाखाओं के माध्यम से भी जमा की गई।

37 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप.....

शिकायत के अनुसार, जालसाजों ने अलग-अलग बैंक खातों और फोनपे के जरिए लगातार रकम की मांग की। कुल 37,61,566 रुपए ट्रांसफर कराए गए, जबकि 61,143 रुपए ही वापस किए गए।

इस तरह पीड़ित के अनुसार उसे 37,00,423 रुपए का नुकसान हुआ।

गोवा कैबिनेट का ऐतिहासिक कदम- गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा का प्रस्ताव

पणजी।

गोवा कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परवर्तन निषेध विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जबरन, दबाव, लालच, धोखाधड़ी या शादी के मकसद से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है। प्रस्तावित कानून के तहत इसतरह के मामलों में दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है।

विधेयक प्रावधान करता है कि यदि कोई शादी केवल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई हो, तब उस शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। धर्मांतरण में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यदि धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तब यह सजा 5 से 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ सकती है।

मुख्य सचिव वी. कंडावेलू ने इस कानून के उद्देश्य पर कहा कि इसका मकसद कमजोर और भोले-भाले लोगों को अनुचित तरीकों से होने वाले धर्मांतरण से बचाना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।

अब कुत्ता जनता पार्टी ने किया ट्रेंड, केजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे छात्र

-बीपीएससी विवाद के बीच परीक्षा नियंत्रक की 'हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार' वाली टिप्पणी पर भड़के अभ्यर्थियों ने यूं दिया जवाब

पटना।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच छात्रों के विरोध का एक अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर सामने आया है। बीपीएससी के एक अधिकारी की टिप्पणी से नाराज अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अपनी एक 'पार्टी' बना ली है, जिसका नाम 'कुत्ता जनता पार्टी' (केजेपी) रखा गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवा हाथों में बैनर लेकर 'कुत्ता जनता पार्टी जिंदाबाद' के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे बैनर पर लिखा है- 'कुत्ता जनता पार्टी- केजेपी- बीपीएससी ने छात्रों की तुलना कुत्तों से की, ये अपमान हम नहीं सहेंगे।' छात्रों का कहना है कि अधिकारी की टिप्पणी से उन्हें अपमानित महसूस हुआ और इसी के विरोध में उन्होंने यह नाम अपनाया है। ऐसे शुरू हुआ था विवाद दरअसल, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभ्यर्थियों की मांगों से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा को प्रीलिम्स और मेंस, दो चरणों में कराने की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कुछ छात्रों का आरोप है कि नई व्यवस्था से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। जब अधिकारी से प्रदर्शन और आयोग के फैसले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आयोग के फैसले पर आपत्ति है, वे कोर्ट क्यों नहीं जाते। इसी दौरान उन्होंने एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार।' इसके बाद उनका बयान विवाद का कारण बन गया। इस पर अधिकारी का कहना था कि उन्होंने महज एक प्रचलित कहावत का इस्तेमाल किया था। हालांकि, छात्रों और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से जोड़कर देखा और आरोप लगाया कि उनकी तुलना कुत्तों से की गई है। छात्रों

ने निकाला विरोध का अनोखा तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आतंकवाद के लिए खाद पानी है नशीले द्रव्यों की तस्करी!

भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विज़न डॉक्यूमेंट 2026 - 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तस्करी की गुप्त सूचनाएं दे सकते हैं।

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

भारत में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर संकट बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों - पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित है। इस संवेदनशील स्थिति के कारण देश में सीमा पार से बड़े पैमाने पर अवैध नशीले पदार्थों की आमद हो रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी में भारत की भौगोलिक स्थिति भी खासा जिम्मेदार है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार से सटी खुली और जटिल जमीनी सीमाएं निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती है ।तस्करों द्वारा गुजरात और दक्षिणी राज्यों के विशाल तटीय क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है ।अब नशे के सौदागर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं डार्कनेट क्रिप्टो करेंसी और सीमा पार से ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का बढ़ता प्रयोग खतरा बढ़ा रहे हैं वहीं पारंपरिक अफीम-गांजे के स्थान पर हेरोइन, कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे घातक रसायनों सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता चलन भी समस्या बन रहा है।

आपको बता दें कि देश में नशे और नशीले पदार्थों की तस्करी ने एक बार फिर केन्द्र और राज्यों की सरकारों को स्तब्ध किया है। नशीले पदार्थों की यह तस्करी का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के माध्यम से सीमा पार से ड्रोनों के ज़रिये किया जाता है। नशे को लेकर किये गये एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान एक प्रकार से नशीले पदार्थों के भण्डारण का केन्द्र बन गया है जहां से इन पदार्थों का बहुत बड़ा भाग भारत के पंजाब प्रांत में ड्रोनों के ज़रिये खपाया जाता है। भारत से फिर यह सामान तस्करी के ज़रिये कई अन्य देशों में भेजा जाता है जहां इसकी बड़ी मांग होती है। पाकिस्तान से भारत में पंजाब सीमा के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी यूं तो दशकों पूर्व से की जाती आ रही है। कभी नावों के माध्यम से, कभी सुरंगों के ज़रिये पाकिस्तानी पंजाब के सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम और हेरोइन की तस्करी की जाती रही है। तथापि, आजकल नावों का कार्य ड्रोनों से लिया जाने लगा है। ड्रोनों के ज़रिये पाकिस्तानी सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम, हेरोइन के साथ हथियारों की खेप भेजना जैसे आम बात हो गई है।वैसे तो नशे के लिए अफीम, चरस, कोकीन आदि अनेकानेक द्रव्यों एवं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है किन्तु वर्तमान में हेरोइन सर्वोत्तम नशीला पदार्थ बन गया है। हाल ही में एक और बड़ा खतरनाक नशीला पदार्थ आईस भी बड़ी चर्चा में आया है। विगत कई वर्षों से हेरोइन की तस्करी और इसके सेवन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका बड़ा प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है कि इन दिनों सीमाओं पर विशेष सुरक्षा चौकसी होने के बावजूद तस्करी से बरामद होने वाली खेपों की संख्या और मात्रा बढ़ गई है। इसके लिए तस्करों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों की निरन्तर चौकसी और सतर्कता के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले पांच वर्षों में पंजाब सीमा पर ड्रोन तस्करी की घटनाएं बढ़ कर तीन से 304 प्रति वर्ष तक हो गई हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में स्थितियों की गम्भीरता को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस एक कठोर टिप्पणी से बेहतर समझा जा सकता है कि नशे का यह सम्पूर्ण कारोबार महज़ एक आपराधिक कार्य मात्र नहीं रह गया, अपितु राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

यूं तो नशे के सेवन और नशीले पदार्थों की तस्करी से गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेश बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं किन्तु पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्या एक गम्भीर संकट के रूप में उभर रही है। पंजाब सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत प्रदेश का पुलिस तंत्र युवाओं को इस महारोग से बचाने के लिए भरसक यत्न कर रहा है किन्तु यह समस्या एक ऐसे बिगड़ैल घोड़े के समान हो गई है कि जिसकी नाक में आसानी से नकेल नहीं डाली जा सकती।

अभी हाल में अमृतसर के थाना लोपोके क्षेत्र में सीमा पार से आई लगभग 180 करोड़ रुपये की 19 किलो हेरोइन के साथ महिला सहित तीन तस्करों को हिरासत में लिया गया। नशा तस्करी में यह भी एक नई प्रवृत्ति सामने आई है कि अवयस्क बालकों को थोड़े से लालच के वशीभूत इस गैर-कानूनी कार्य में शामिल किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों की शमूलियत से इस अवैध क्रिया-कलाप को एक नया मोड़ मिला है। पिछले कुछ समय में पंजाब में पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े कई अवयस्कों और महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। प्रदेश सरकार ने अपने ऑपरेशन प्रहार के दौरान लगभग 4000 तस्करों-गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी किया है। इतने बड़े स्तर पर तस्करों की गिरफ्तारी, इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेपों की बरामदगी से तस्करी पर काबू पाये जाने की सम्भावना बनती है, किन्तु इतनी बड़ी बरामदगी और बड़े स्तर पर युवाओं और अव्यवस्कों की भागीदारी से इस कारोबार की भीषणता भी जाहिर होती है। पंजाब सरकार के प्रहार अभियानों और प्रदेश के पुलिस तंत्र की सक्रियता से बेशक प्रदेश के लोगों के मन में आशा और विश्वास की एक लकीर उपजते दिखाई देती है, किन्तु हम समझते हैं कि लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस तंत्र की सक्रियता कागजों में भी हो, किन्तु धरातल पर उसे दिखाई भी अवश्य देना चाहिए। कानून के हाथ लम्बे होते हैं, किन्तु ये हाथ अपराधियों और तस्करों के गिरेबान तक पहुंचने भी तो चाहिएं। कुछ भी हो अथवा कुछ भी किया जाए, देश को नशीले पदार्थों की तस्करी की इस लानत से मुक्ति मिलनी चाहिए।

देश की कामकाजी आबादी खासकर युवा और कालेज छात्र छात्राएं स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आकर मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु हो रहे हैं ।नारको-टेररिज्म जड़ जमा रहा है। ड्रग्स की तस्करी से होने वाली अवैध कमाई का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद की फंडिंग में किया जाता है। नशे की दैनिक तलब पूरी करने के लिए युवा चोरी, लूटपाट और संगठित अपराधों के रास्ते पर जा रहे हैं। अवैध काले धन और हवाला कारोबार के कारण देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है।

ऐसा नहीं है कि सरकार को नशीले द्रव्यों की तस्करी और उसके कारण हो रही बर्बादी का भान नहीं है सरकार ने इस ओर नियंत्रण के लिए की प्रभावी कदम उठाए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है।

भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विज़न डॉक्यूमेंट 2026 - 2029 जारी किया है ।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है ।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तस्करी की गुप्त सूचनाएं दे सकते हैं। तस्करों की संपत्तियों को कुर्क करने और पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत आदतन अपराधियों को बिना जमानत जेल में रखने की कार्रवाई तेज कर दी गई है अभी और अधिक असरदार कारवाई और सख्ती की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

ज़हर बांटते उद्योग

कुछ उद्यमी मुनाफे की अंधी हवस में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को साफ किए बिना ही जलधाराओं में बहा देते हैं। जबकि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण व नदी-नालों को प्रदूषित न करें। हिमाचल प्रदेश स्थित बद्दी-नालागढ़ इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां नदियों में ज़हरीले रसायन लगातार बहाती रही हैं। यह प्रदूषणकारक कचरा सिरसा नदी में बहा दिया जाता है, जो कालांतर सतलुज नदी में चला जाता है। यही वजह है कि आज सतलुज का प्रदूषित पानी जो चेतावनी दे रहा है उसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। इसी आने वाले संकट के मद्देनजर ही बद्दी-नालागढ़ इलाके की अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो मामले की गंभीरता को ही दर्शाता है। निस्संदेह, यह संकट कोई नई समस्या नहीं हैं। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम व कानूनों को लागू करने में तंत्र की बार-बार होने वाली विफलता को ही दर्शाता है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के प्रामाणिक रिकॉर्ड कई सालों से मौजूद हैं। दरअसल, यह जहरीला कचरा इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाली सिरसा नदी में डाल दिया जाता है। सिरसा नदी इन प्रदूषक तत्वों को आगे की ओर बहा ले जाती है। कालांतर यह सतलुज नदी में जाकर मिल जाता है। इस बाबत कई बार जांच भी की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बिना ट्रीट किए गए रसायनयुक्त कचरे व ठीक से ट्रीट न किए गए कचरे के बारे में उल्लेख किया गया है। ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों तथा ट्रीटमेंट सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया है। दरअसल, फार्मास्युटिकल प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पारंपरिक ढंग से ट्रीटमेंट करने वाले सिस्टम से सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व और एंटीबॉयोटिक के अवशेष पूरी तरह से नहीं हट पाते हैं। दरअसल, हाल के प्रकरण से एक और परेशान करने वाली विरोधीभासी बात सामने आई है। इस बाबत सूचना मिली थी कि रोपड़ हेडवर्क्स पर भारी मात्रा में जमा कचरे को नदी के बहाव की दिशा में बेफिक्री से छोड़ दिया गया। निस्संदेह, यदि यह कचरा नुकसानदायक था, तो इसे नदी में छोड़ने से समस्या महज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ही हुई है। कायदे से हेडवर्क्स में जमा कचरे की वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निगरानी की जानी चाहिए थी। सही मायने में प्रदूषणकारक कचरे को ठिकाने लगाने से पहले उसके सैंपल लेकर उसकी जांच-पड़ताल की जानी जरूरी थी। निश्चित रूप से यह संकट बड़ा है और तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए था। वास्तव में इस मामले को हिमाचल बनाम पंजाब के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि दोनों सरकारें मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का वास्तविक स्रोत तलाशें क्योंकि अभी तक कचरे के असली स्रोत का पता नहीं चल सका है। यही वजह है कि अभी अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन यह एक हकीकत है कि अज्ञात इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, दोषी होने का सबूत नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि पंजाब और हिमाचल के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी मिलकर साझी जांच करें। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चाहिए कि वह इसकी स्वतंत्र रूप से निगरानी करे।

यूपीआई@10: भुगतान की दुनिया में भारत का नया अध्याय

दस साल की इसकी यात्रा बताती है कि जब तकनीक को आम आदमी की जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। सच तो यह है कि यूपीआई के दस वर्ष केवल किसी डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता के दस वर्ष नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और डिजिटल परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा हैं। इसने भुगतान को सरल, त्वरित और व्यापक बनाया तथा छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक को एक साझा डिजिटल मंच दिया।

(लेखक- सुनील कुमार महला)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा विकसित यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की एक तत्काल डिजिटल भुगतान प्रणाली है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह माध्यम है, जिसके माध्यम से मोबाइल फोन से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत में यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने मुंबई में लॉन्च किया था ।हालांकि, आम लोगों के लिए यूपीआई सेवाएँ अगस्त 2016 से व्यापक रूप से उपलब्ध हुईं। इस साल यानी कि वर्ष 2026 में यूपीआई ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान को पूरी तरह बदल दिया है ।सच तो यह है यूपीआई आज भारत के दैनिक डिजिटल भुगतान तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज यूपीआई का उपयोग हर कहीं पर दुकानों और बाजारों में सामान खरीदने, रेस्तरां व होटल के बिल चुकाने, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल रिचार्ज, बिजली-पानी-गैस जैसे उपयोगिता बिलों के भुगतान, रेल-बस-विमान टिकट बुकिंग, स्कूल-कॉलेज की फीस, अस्पतालों में भुगतान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक डिजिटल लेन-देन में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। यानी आज यूपीआई भारत के दैनिक जीवन में नकद भुगतान के एक आसान, तेज और सुविधाजनक डिजिटल विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है। बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि अन्य देशों की तुलना में भारत का यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में असाधारण पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2026 में यूपीआई दुनिया के लगभग 49त्न रियल-टाइम भुगतान लेन-देन को संभाल रहा है, यानी दुनिया में होने वाले लगभग हर दो तत्काल डिजिटल भुगतानों में एक यूपीआई के माध्यम से होता है। भारत में इसकी मात्रा भी तेजी से बढ़ी है और वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई पर करीब 24,162 करोड़ लेन-देन हुए। मई 2026 में अकेले यूपीआई ने 23,201.93 मिलियन यानी लगभग 2,320 करोड़ लेन-देन किए, जिनका कुल मूल्य करीब ₹29.90 लाख करोड़ रहा। इस तुलना में भारत की खासियत यह है कि यूपीआई केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और आम नागरिक तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई अब 11 देशों में भी उपलब्ध है और वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण बन चुका है। अन्य शब्दों में कहें तो वर्ष 2016 में शुरू हुई यह व्यवस्था आज देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है।

पहले जहां डिजिटल भुगतान सीमित था, वहीं अब चायवाले, सब्जीवाले, छोटे दुकानदार और आम लोग भी आसानी से यूपीआई से पैसे ले-दे रहे हैं। एक दशक में यूपीआई लेन-देन में हुई भारी वृद्धि इसकी लोकप्रियता और लोगों के भरोसे को दिखाती है ।यूपीआई से बैंकिंग आसान, तेज और सुविधाजनक हुई है। लोगों को नकदी निकालने के लिए बैंक जाने या लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत कम हुई है। आज पलभर में ही दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, नकदी कम रखने से चोरी और लूट का जोखिम भी घटा है। डिजिटल भुगतान से लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिली है ।यूपीआई की सफलता के पीछे डिजिटल इंडिया अभियान और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार भी महत्वपूर्ण रहा है। देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ने से डिजिटल भुगतान आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि दूसरे देश भी यूपीआई जैसी भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं ।हालांकि, अभी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। बैंक का सर्वर डाउन होना, अधिक ट्रैफिक के कारण भुगतान अटकना और गलती से गलत व्यक्ति को पैसे भेज देना जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी है। कुल मिलाकर, यूपीआई केवल पैसे भेजने और लेने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल प्रगति और आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका है। दस साल की इसकी यात्रा बताती है कि जब तकनीक को आम आदमी की जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। सच तो यह है कि यूपीआई के दस वर्ष केवल किसी डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता के दस वर्ष नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और डिजिटल परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा हैं। इसने भुगतान को सरल, त्वरित और व्यापक बनाया तथा छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक को एक साझा डिजिटल मंच दिया। आज दुनिया के अनेक देश यूपीआई में रुचि ले रहे हैं और कई देशों में इसका उपयोग भी शुरू हो चुका है। यूपीआई ने साबित किया है कि भारत केवल डिजिटल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया को बड़े पैमाने पर अपनाने योग्य डिजिटल समाधान देने वाला देश भी है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता का अगला पड़ाव केवल लेन-देन की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, समावेशी और वैश्विक डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार)

कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है जीव

ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीवविशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है।

चूंकि इस प्रकार वह आत्मा देहांतरण कर जाता है, अत उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मो का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मो के सारे फल बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्वों- ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शात हैं, कर्म शात नहीं है।

परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान हैं- भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं- जब वे इस भौतिक वि में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे भगवद्गीता में बोलते हैं।

भौतिक कल्मष-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य-जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अत- भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित (दूषित) नहीं हैं। भगवद्गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है।

विचार मंथन

नर्सिंग छात्रों के साथ 5 साल से खिलवाड़, जिम्मेदार कौन?

(लेखक- सनत जैन)

मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा पिछले पांच वर्षों से ऐसी उलझी पड़ी है, जिसका सिरा तलाश करते-करते विद्यार्थी थक गए। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में उलझी होने के कारण इसकी पूंछ का सिरा भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। व्यवस्था में सुधार होने की कल्पना करना भी अब व्यर्थ लगने लगा है। कभी नर्सिंग काउंसिल कटघरे में खड़ी दिखाई देती है, कभी विश्वविद्यालय, कभी सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में आती हैं। कभी कॉलेजों के निरीक्षण तथा मान्यता पर सवाल उठते हैं। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। मामला पिछले कई सालों से हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया। जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अंततः नर्सिंग छात्रों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। एडमिशन और फीस के नाम पर छात्र हर साल ठगे जा रहे हैं। समय पर परीक्षा नहीं हो रही है। किस नर्सिंग कॉलेज को मान्यता है, किसको नहीं है यह भी छात्रों को पता नहीं चल पाता है। हर स्तर पर भारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं। इसका कोई इलाज हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सरकार के पास नहीं है। हाथ में फीस की रसीद और आंखों में अपने भविष्य का सवाल लेकर छात्र यहां से वहां भटक रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है, इस पूरे विवाद की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? सरकार नहीं, नर्सिंग काउंसिल नहीं, विश्वविद्यालय नहीं और वे कॉलेज भी नहीं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कीमत चुका रहा है, वह विद्यार्थी, जिसने नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखा था। जिन विद्यार्थियों ने 2020-21 के आसपास नर्सिंग में प्रवेश लिया, उनकी पढ़ाई सामान्य परिस्थितियों में 3 वर्षों में पूरी हो जानी चाहिए थी। पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश, मान्यता, परीक्षा, परिणाम और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों में फंसा हुआ है। विद्यार्थी की उम्र बढ़ गई, शिक्षा पर होने वाला खर्च बढ़ता गया। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी शिक्षा कब पूरी होगी, कब वह नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। यह स्थिति केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, यह युवा पीढ़ी के साथ अन्याय है। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवसाय में लोगों को प्रशिक्षित नर्स पिछले कई वर्षों से नहीं मिल पा रही हैं। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में तेजी के साथ बढ़ गया है। प्रशिक्षित नर्स की मांग विदेश में भी बनी हुई है। नर्सिंग के छात्र हर जगह से ठगे जा रहे हैं। उनका करियर बर्बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में नर्सिंग से जुड़े मामले लंबे समय से सुनवाई में हैं। सीबीआई जांच तक हुई। कॉलेजों के निरीक्षण, अस्पतालों की उपलब्धता, मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल उठे। कागजों पर अस्पताल दिखाकर मान्यता लेने जैसी गड़बड़ियां हुईं, तो यह केवल किसी निजी कॉलेज की गलती नहीं मानी जा सकती। सवाल यह है, निरीक्षण करने वाली व्यवस्था ने क्या देखा? किसने रिपोर्ट दी? किसने मान्यता दी? किसने प्रवेश की अनुमति दी? अगर अस्पताल था ही नहीं, तो निरीक्षण किस आधार पर हुआ? अगर कॉलेज मानकों पर खरा नहीं उतरता था, तब विद्यार्थियों को प्रवेश क्यों मिला? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था, तो पांच साल बाद विद्यार्थी अदालतों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? विडंबना देखिए, एक ओर प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की देश और विदेश में भारी कमी बनी हुई है, अस्पतालों को प्रशिक्षित नर्सों की जरूरत है। दूसरी ओर हजारों-लाखों विद्यार्थियों का समय प्रशासनिक और कानूनी भूलभुलैया में फंस गया है। पिछले 5 साल से हाईकोर्ट में मामला होते हुए नर्सिंग के छात्र आज भी यहां से वहां भटक रहे हैं। उन्हें किसी भी स्तर पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह कैसी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें मरीज को नर्स नहीं मिलती और नर्सिंग विद्यार्थी को शिक्षा पूरी करने का अवसर नहीं मिलता? हर जगह लापरवाही और लूट देखने को मिल रही है।

सबसे गंभीर प्रश्न न्यायिक जवाबदेही का भी है। जब मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जांच कर चुकी है। वर्षों से सुनवाई चल रही है, तब क्या केवल तारीखें ही समाधान हैं? न्याय में देरी का सबसे बड़ा नुकसान उस विद्यार्थी को होता है, जिसके जीवन के पांच वर्ष वापस नहीं आ सकते हैं। किसी विद्यार्थी के पांच वर्ष केवल कैलेंडर के पांच पन्ने नहीं होते। वे उसकी उम्र, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आर्थिक निवेश और परिवार की उम्मीदों के पांच वर्ष होते हैं। अब समय आ गया है। सरकार, नर्सिंग काउंसिल, विश्वविद्यालय और संबंधित संस्थाएं एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की राजनीति बंद करें। दोषियों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोषी कॉलेज और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय दोषी हो तो उन्हें दंडित करने की कार्रवाई हो। विद्यार्थी निर्दोष हैं, उनके भविष्य की तत्काल सुरक्षा की जाए। नर्सिंग शिक्षा को भ्रष्टाचार, मान्यता और प्रशासनिक विवादों का अखाड़ा बनाना केवल विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यायपालिका की विश्वसनीय और प्रभावशीलता को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी साख बनाए रखने की दिशा में काम करना होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोने-चांदी की कीमतों में उछाल

नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की अप्रत्याशित रूप से अधिक बायबैक की घोषणा के बाद से ही सोने की कीमतें तीन महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गयीं। वैश्विक बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोना 4,700 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया। चांदी भी 69 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है। इस तेजी से निवेशकों का ध्यान एक बार फिर सुरक्षित निवेश मानी जाने वाली इन धातुओं की ओर बढ़ा है।

वहीं घरेलू बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी की वायदा कीमतों में उछाल देखा तेजी रही। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 1,63,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब, जबकि चांदी का भाव 2,45,700 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रहा था।

एमसीएक्सा पर सोने के बेंचमार्क अक्टूबर अनुबंध की शुरुआत तेजी के साथ हुई। यह 320 रुपये की बढ़त के साथ 1,63,202 रुपये के भाव पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,62,882 रुपये था। वर्तमान समय में, यह अनुबंध 254 रुपये की तेजी के साथ 1,63,136 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार के दौरान ये 1,63,202 रुपये के उच्च स्तर और 1,62,021 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचा।

इसी प्रकार चांदी के वायदा भाव में भी बड़ी तेजी रही। एमसीएक्स पर सितंबर अनुबंध 1,456 रुपये की बड़ी बढ़त साथ 2,45,583 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,44,127 रुपये था। दिन के दौरान इसका उच्चतम स्तर 2,46,180 रुपये और न्यूनतम स्तर 2,45,430 रुपये रहा। चांदी के वायदा भाव इस साल 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोने चांदी के वायदा भाव में सकारात्मक रुख जारी है। सोने का भाव 4,715.70 डॉलर प्रति औंस पर खुला और खबर लिखे जाने तक 10.90 डॉलर की तेजी के साथ 4,705.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसका पिछला बंद भाव 4,694.50 डॉलर प्रति औंस था।

ईरान-अमेरिका युद्ध से परेशान एनआरआई भारत में खरीद रहे महंगे मकान

मुंबई, बेंगलूरु और एनसीआर में 1 से 5 करोड़ के अपार्टमेंट करा रहे बुक

नई दिल्ली।

ईरान युद्ध के चलते प्रवासी भारतीय भारत में महंगे मकान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक करीब छह महीने से जारी ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के बीच एनआरआई भारत में लक्जरी मकान खरीदने के लिए बातचीत बढ़ा रहे हैं। पूर्वंकरा सीईओ ने कहा कि एनआरआई की दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में हमारी प्री-सेल्स में एनआरआई की हिस्सेदारी 9 फीसदी थी, जो चौथी तिमाही में बढ़कर 13 फीसदी और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 15 फीसदी तक पहुंच गई है।

खास बात यह है कि एनआरआई की तरफ से आ रही मांग का करीब 87 फीसदी हिस्सा पश्चिम एशिया से है। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रहने वाले एनआरआई 'आज भारत को निवेश का स्थिर और लंबे समय का ठिकाना मान रहे हैं। इस साल 28 फरवरी को लड़ाई छिड़ने के बाद से जीसीसी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले होते रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपरों और अधिकारियों का कहना है कि एनआरआई मुंबई, बेंगलूरु और एनसीआर में 1 से 5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट बुक करा रहे हैं। लोढ़ा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए कंपनी की अर्निंग्स कॉल के दौरान अनुमान लगाया कि यह रुझान पिछले साल से उलटा हो सकता है। उन्होंने कहा कि विदेश में उथल-पुथल के कारण एनआरआई भारत में सुरक्षित ठिकाना तलाशेंगे। हमें उम्मीद है कि आव्रजन से जुड़ी वजहों से अमेरिका में रहने वाले खरीदार भी ऐसा ही करेंगे। पिछले साल भारत से करीब 35,000 करोड़ रुपए का निवेश दुबई के रियल एस्टेट में हुआ था।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 183, निफ्टी 126 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। आज कारोबार के दौरान एफएमसीजी और ऑटो शेयरों के साथ ही आईटी में भी गिरावट रही जिससे भी बाजार धारणा कमजोर हुई। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 183.15 अंक गिरकर 77,472.94 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 126.80 नीचे आकर 24,207.75 पर बंद हुआ।

आज सुबह सेंसेक्स बढ़त के साथ 77,892.10 पर खुला। वहीं, निफ्टी अपने 7.40 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,341.95 पर खुला। व्यापक बाजार में भी मिश्रित कारोबार देखने को मिला, जहां निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में गिरावट रही। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में तेजी दर्ज की गई।

निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी का प्रदर्शन भी खराब रहा।

वहीं, निफ्टी मेटल, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी सीमेंट का प्रदर्शन बेहतर रहा। आज कोटक

महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त रही, जबकि भारती एयरटेल, पावरग्रिड, इंफोसिस, एलएंडटी, नेस्ले इंडिया और श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं इससे पहले आज सुबह शुरुआती घंटों में ही सेंसेक्स 240 अंक बढ़कर 77,900 के स्तर के करीब पहुंच गया जबकि निफ्टी 24,300 अंक ऊपर आया। दूसरी ओर एशिया-प्रशांत के ज्यादातर बाजार भी बढ़त पर रहे।

अगले दशक में भारत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 4.5 लाख करोड़ के निवेश की दरकार

नई दिल्ली। देश में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के पांच साल बाद 1996 में अर्थशास्त्री राकेश मोहन ने वित्त मंत्रालय को अहम दस्तावेज सौंपा। इस दस्तावेज ने भारत के अवसंरचना या बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परिभाषा ही बदल दी। मोहन उस समय राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के महानिदेशक हुआ करते थे। भारतीय अवसंरचना रिपोर्ट शीर्षक नाम से मोहन के इस दस्तावेज में वैश्विक रुझानों और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के भारत की महत्त्वाकांक्षाओं का जिक्र किया गया था। इस दस्तावेज में उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की ज्यादा भागीदारी पर जोर दिया जिसमें सरकार का दबदबा था। इस रिपोर्ट ने उन कई सुधारों का रास्ता भी साफ हो गया जो भारत में आने वाले सालों में अपनाए गए थे।रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि अगले दशक में भारत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की दरकार होगी। साथ ही, इसमें कहा गया था कि निजी निवेश की हिस्सेदारी 5 फीसदी से बढ़ाकर 44 फीसदी करने की जरूरत है। इसके बाद के सालों में सरकार को एहसास हुआ कि जर्जर हो रहे अवसंरचना क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलना बहुत जरूरी है।

इसके बाद खासकर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दौरान कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं जिनके जरिये संपर्क को बढ़ावा मिला। इनमें 'स्वर्णिम चतुर्भुज' परियोजना भी शामिल थी। उस समय के कुछ जानकारों ने इस परियोजना को 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए 'ग्रांड ट्रंक रोड' के बाद अपनी तरह का सबसे बड़ी परियोजना बताया था।

देश में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट, मजदूरों की कमी से कई काम नहीं हो पा रहे पूरे

कंपनियों को हो रहा घाटा 10 फीसदी घटी कमाई, देरी से बढ़ रही प्रोजेक्ट की लागत,

नई दिल्ली, ।

देश में सड़क, रेलवे, मेट्रो, बिजली और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कंपनियों को नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आ रही है। काम तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। इसका असर प्रोजेक्ट की रफ्तार से लेकर कंपनियों की कमाई पर पड़ने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में देश की 13 बड़ी लिस्टेड इंफ्रा कंपनियों को मिले नए ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले 63 फीसदी बढ़े, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों की कुल आमदनी पिछले साल के आसपास ही रही और पिछली तिमाही के मुकाबले 10 फीसदी घट गई।

रिपोर्ट के मुताबिक किसी कंपनी को 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल जाना और उससे कमाई होना एक बात नहीं है। कंपनी की कमाई तब होती है, जब वह जमीन पर काम करती है। सड़क बनती है, पुल तैयार होता है या रेलवे से जुड़ा काम करती है। इसके लिए मशीनों और इंजीनियरों के साथ बड़ी संख्या में मजदूर चाहिए होते हैं। रिपोर्ट में बताया कि पहली तिमाही में राज्यों के चुनाव के कारण मजदूरों से जुड़ी परेशानी देखने को मिली। इसका असर काम की रफ्तार पर पड़ा यानी कंपनियों के पास ऑर्डर थे, लेकिन मजदूरों की कमी के कारण काम की रफ्तार धीमी रही।

मजदूरों की कमी से कंपनियों के सामने एक और परेशानी खड़ी होती है। जब काम ज्यादा हो और मजदूर कम मिलें तो मजदूरी बढ़ जाती है यानी कंपनी को वही काम कराने के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर मजदूर समय पर नहीं मिलते तो प्रोजेक्ट पूरा होने में भी ज्यादा समय लगता है। इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता है। हालांकि कंपनियों की कमजोर तिमाही के लिए सिर्फ मजदूरों की कमी जिम्मेदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी कंपनियों का खर्च बढ़ाया है। इसके साथ मजदूरी की लागत भी बढ़ी है। नतीजा 13 कंपनियों का कामकाजी मुनाफे का मार्जिन पिछले साल के मुकाबले करीब 1.10 फीसदी घटकर 10 फीसदी रह गया। वहीं शुद्ध मुनाफे से जुड़ा मार्जिन करीब 1.30 फीसदी घटकर 4 फीसदी रह गया है।

अगर मजदूरों की परेशानी लंबे समय तक रहती है तो इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। सड़क, पुल, रेलवे लाइन, मेट्रो या दूसरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में ज्यादा समय लग सकता है। काम लंबा खिंचा तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि देश के सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट मजदूरों की कमी से अटक जाएंगे। अलग-अलग कंपनी, राज्य और प्रोजेक्ट पर इसका असर अलग हो सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

न्यूयार्क ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गयी है। कीमतों में ये गिरावट वैश्विक आपूर्ति मार्ग होर्मुज पर तनाव में कमी से आई है। कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेज गिरावट दर्ज की गई। इससे अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड 2 फीसदी ने फिसलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब आ गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी लगभग 2.25 फीसदी की गिरावट के साथ ही 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण विश्व के प्रमुख तेल आपूर्ति मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम होनो है जिससे जहाजों का आवागमन बेहतर हुआ है। ईरान और ओमान के बीच इस प्रमुख् समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही को बेहतर बनाने बातचीत जारी है। , इन देशों के बीच चल रही वार्ताओं से यह उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में तेल वाहक जहाजों की आवाजाही आसान हो जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देश एक अस्थायी समुद्री मार्ग स्थापित करने और समुद्र में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटाने पर भी विचार कर रहे हैं। इन सकारात्मक घटनाक्रमों ने बाजार में तेल आपूर्ति की कमी के डर को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे निवेशकों का रुख बिकवाली की ओर मुड़ गया है।बुधवार सुबह (भारतीय समयानुसार लगभग 8 बजे), डब्ल्यूटीआई क्रूड का अक्टूबर वायदा 2 डॉलर यानी 2.43 फीसदी गिरकर 80.36 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

तमिलनाडु में बच्चों को सोने की अंगूठी- दिग्गज ज्वैलर्स सिर्फ एक पैसे में बनाएंगे

योजना में 22 कैरेट सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी

चेन्नई,।

तमिलनाडु सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम' योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को एक ग्राम, 22 कैरेट सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी। इस विशाल परियोजना को साकार करने के लिए, दो प्रमुख आभूषण कंपनियों, जोयालुक्कास और कल्याण ज्वेलर्स को लाखों अंगूठियां बनाने का ठेका दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दिग्गज ज्वैलर्स, जो आमतौर पर ग्राहकों से भारी मेकिंग चार्ज वसूलते हैं, थलापति विजय सरकार से प्रति अंगूठी केवल 1 पैसे का सांकेतिक सेवा शुल्क लेने वाले है। मामा की सोने की अंगूठी योजना' नाम से जानी जाने वाली पहल, राज्य में प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तमिल संस्कृति में नवजात शिशु के आगमन पर मामा द्वारा उपहार देने की परंपरा से प्रेरित यह योजना, मुख्यमंत्री थलपति विजय की पार्टी के चुनावी वादे का हिस्सा है। विजय सरकार ने योजना के लिए प्रति वर्ष 755.83 करोड़ का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया है, जो इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दिखाता है।यह असाधारण 1 पैसे का सेवा शुल्क केवल मेकिंग चार्ज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निर्माण से लेकर अस्पताल तक अंगूठियों के सुरक्षित परिवहन का बीमा, साथ ही 22 कैरेट सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग का खर्च शामिल है। सोने की बाजार कीमत का भुगतान विजय सरकार अलग से करेगी।

इस ठेका को पाने के लिए कुल 11 आभूषण कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन जोयालुक्कास और कल्याण ज्वैलर्स ने सबसे कम, यानी 1 पैसे प्रति अंगूठी की दर पेश की।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 9 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.31 पर बंद हुआ आज सुबह रुपया 95.40 पर खुला था। कच्चे तेल में आई गिरावट से भी रुपया मजबूत हुआ है। वहीं गत दिवस रुपया गिरावट पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सरकारी बैंकों के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लगातार हस्तक्षेप से रुपये की गिरावट को अधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिली। इससे एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी और ईरान को लेकर फिर बढ़ी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद रुपया सीमित दायरे में रहा।

बीमा सेक्टर में कमीशन से लेकर बेचने तक के बदल सकते हैं नियम, बदलाव की है तैयारी

बीमा सेक्टर में प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसी की संख्या नहीं

नई दिल्ली, ।

लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आईआरडीएआई की नजर अब बीमा कंपनियों के कमीशन, बैंकों के जरिए पॉलिसी बेचने के तरीके और ग्राहकों को सही पॉलिसी देने जैसे मुद्दों पर है। अगर ये बदलाव होते हैं तो इसका असर एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रोडेंटल लाइफ और एक्सिस मेक्स लाइफ जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है। बीमा सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसी की संख्या नहीं।

बता दें वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच नई पॉलिसी की संख्या हर साल औसतन 1.3 फीसदी घटी। वहीं नई पॉलिसी से मिलने वाला प्रीमियम करीब 8.9 फीसदी सालाना बढ़ा। इस दौरान कंपनियों का कमीशन खर्च भी करीब 14.5 फीसदी सालाना बढ़ा है यानी कंपनियों की ग्रोथ ज्यादा ग्राहक जोड़ने के बजाय महंगी पॉलिसी बेचने से आ रही है। वित्त वर्ष 2025 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने करीब 60,800 करोड़ रुपए कमीशन दिया। अब इस बात पर चर्चा है कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाले पैसे का तरीका बदला जाए। मतलब कमीशन का कुछ हिस्सा इस बात से जोड़ा जा सकता है कि ग्राहक कितने समय तक पॉलिसी चालू रखता है। इससे सिर्फ पॉलिसी बेचने के बजाय उसे लंबे समय तक जारी रखने पर भी जोर बढ़ेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक 13वें महीने तक औसतन करीब 73.6 फीसदी पॉलिसी जारी रहती हैं। 37वें महीने तक यह आंकड़ा घटकर करीब 58.5 फीसदी रह जाता है यानी बड़ी संख्या में लोग कुछ साल बाद पॉलिसी छोड़ देते हैं। इसकी वजह महंगा प्रीमियम या ग्राहक की जरूरत के हिसाब से सही पॉलिसी नहीं मिलना हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के जरिए बीमा बेचने के नियमों में बदलाव हुआ तो एसबीआई लाइफ पर ज्यादा नजर रहेगी। कंपनी के करीब 60 फीसदी एपीई का स्रोत उसकी पैरेंट बैंक से जुड़ा है।

वहीं एचडीएफसी लाइफ और एक्सिस मेक्स लाइफ पहले से ऐसे मॉडल पर काम करती हैं, जहां पैरेंट बैंक दूसरी बीमा कंपनियों की पॉलिसी भी बेच सकता है। शुरुआत में नए नियमों से बीमा कंपनियों की बिक्री पर कुछ दबाव पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से बेहतर पॉलिसी मिलने और पॉलिसी बीच में छोड़ने के मामले कम होने से इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। फिलहाल ये बदलाव चर्चा में हैं।

अमेरिका ने 'ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट' शुरु किया तो भारत पर भी पड़ेगी मार

भारत का बासमती चावल निर्यात और व्यापार प्रभावित होने का खतरा, व्यापारी परेशान

नई दिल्ली, ।

ईरान से लड़ाई में कोई निर्णायक नतीजा नहीं मिलने के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घेरने के लिए जो 'ऑपरेशन इकनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है, उसकी मार भारत को झेलनी पड़ सकती है। ईरान के साथ पहले ही घटते भारत के व्यापार में अमेरिका के इस कदम से और भी कमी आ सकती है, साथ ही पश्चिम एशिया में मालभाड़े और कच्चे तेल से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपने 'आर्थिक हमले' का पूरा ब्योरा नहीं दिया लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने देशों से तुरंत कदम उठाने को कहा और ईरान के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध की धमकी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेसंट ने कहा कि आने वाले दिनों में नए प्रतिबंधों के ऐलान होंगे, जिनकी जद में एक बड़ा वित्तीय संस्थान भी आ सकता है।

भारत हर साल करीब 50-60 लाख टन बासमती चावल का निर्यात करता है, जिसमें करीब 10 लाख टन चावल ईरान भेजता है। वित्त वर्ष 2026 में भारत से ईरान को कुल 1.3 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ था, जिसमें करीब 60 फीसदी हिस्सा बासमती चावल का था। यहां के बासमती चावल निर्यातकों को डर है कि द्वितीयक प्रतिबंध के कारण ईरान को आपूर्ति और घट सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के प्रमुख चावल निर्यातक ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने और ईरान तक माल पहुंचाने में आ रही दिक्कतों का असर इस साल अप्रैल से ही हमारे बासमती चावल निर्यात पर पड़ रहा है।

आपूर्ति और घटी तो तगड़ी चोट पड़ेगी। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि असली संकट तो तब शुरू होगा जब प्रतिबंधों के कारण यूएई ईरान को बेचे गए चावल की कीमत चुकाना बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर खरीदार यूएई में हैं और अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को हुई आपूर्ति के लिए यूएई के रास्ते होने वाला भुगतान रुका तो समस्या आएगी। कुछ कारोबारियों का मानना है कि ईरान पर प्रतिबंध बार-बार लगते रहे हैं इसलिए निर्यातकों को ईरान तक अपना सामान भेजने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने होंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा बाजार है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जुलाई में मॉनसून सुधार से खरीफ बोआई सामान्य के करीब, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिखी

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में सुधार होने से खरीफ बोआई को सामान्य के करीब लाने में मदद मिली। इससे कृषि क्षेत्र के लिए जोखिम आंशिक रूप से कम हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों के प्रति काफी मजबूती दिखाई है, जिसका संकेत घरेलू मांग में उछाल और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों से मिलता है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जून में सुस्त रहने के बाद जुलाई में काफी सक्रिय दिखा। ऐसे में देश भर के जलाशयों का भंडारण एक दशक के औसत के करीब और पिछले अल नीनो वर्ष 2023 के स्तर से ऊपर रहा। जून के आखिर में बारिश की कमी कुल मिलाकर 38 फीसदी थी जो घटकर जुलाई के अंत तक 13 फीसदी रह गई है।हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस रिपोर्ट में बताई गई बातें लेखकों की निजी राय हैं और वे आरबीआई की राय को नहीं दर्शाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष खरीफ बोआई की अस्थायी प्रगति 2023 के मुकाबले बेहतर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगस्त से सितंबर के लिए देश भर में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में मॉनसून की गतिविधियों में सुधार होने से खरीफ फसलों के रकबे में सुधार हुआ। सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना (ओएमएसएस) की भी घोषणा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन और ट्रैक्टर बिक्री समेत कई संकेतकों से घरेलू मांग दमदार बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वृहद आर्थिक बुनियादी स्थिति दमदार रहने से घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। पहली तिमाही में दिखी यह रफ्तार जुलाई में भी जारी रही। अधिकतर संकेतक विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में तेजी की रफ्तार जारी रहने और वस्तुओं के निर्यात एवं आयात में दो अंकों की वृद्धि को दर्शाते हैं।रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत वृद्धि तीन महीनों की नरमी के बाद सकारात्मक हो गई है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में भी जून में तेज वृद्धि हुई। इसे मुख्य तौर पर विनिर्माण में तेजी से रफ्तार मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और पेय पदार्थों के कारण जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई लेकिन कीमती धातुओं को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति मध्यम बनी रही।

विदेशी यात्रियों की आवाजाही प्रभावित होने के बाद भी भारत में होटलों ने की कमाई

घूमने-फिरने वाली जगहों के होटलों का प्रदर्शन बड़े कारोबारी शहरों के मुकाबले बेहतर रहा

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण विदेशी यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई, फिर भी भारत में होटल की मांग मजबूत बनी रही। घूमने-फिरने, शादियों और बड़े कारोबारी कार्यक्रमों के लिए होटल की मांग ने सेक्टर को सहारा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में होटल सेक्टर की प्रति उपलब्ध कमरे से होने वाली कमाई करीब 10 फीसदी बढ़ी। कमरे का औसत किराया 6 फीसदी बढ़ा और कमरों की भराव दर करीब 2.33 फीसदी बढ़कर 65 फीसदी पहुंची यानी होटल कंपनियां ज्यादा कमरे चढ़ाने के साथ उनका किराया भी बढ़ाने में कामयाब रहीं। निवेशकों के लिए यही इस सेक्टर की सबसे अहम बात है।

रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही में मुंबई और घूमने-फिरने वाली जगहों के होटलों का प्रदर्शन बड़े कारोबारी शहरों के मुकाबले बेहतर रहा। इसके पीछे घरेलू यात्रियों की बड़ी भूमिका रही। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रभावित हुई और विदेशी पर्यटकों की संख्या पर दबाव पड़ा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कारुआना ने ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जीत हासिल की

पहले क्लासिकल गेम के बाद 6-0 की बढ़त

नईदिल्ली, एजेंसी। सेंट लुइस में खेले जा रहे ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026 के खिताबी मुकाबले में ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना ने भारत के आर प्रज्ञानानंदा को हरा दिया। कारुआना ने फाइनल के पहले क्लासिकल गेम में प्रज्ञानानंदा को शिकस्त दी। इस जीत से अमेरिका के कारुआना ने मैच में 6-0 की बढ़त बना ली। मुकाबले में प्रज्ञानानंदा लंबे समय तक बराबरी पर थे, लेकिन 28वीं चाल में हुई गलती के बाद कारुआना ने गेम अपने नाम कर लिया। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में विंसेंट कीमर और वेस्ली सो का पहला क्लासिकल गेम ड्रॉ रहा और दोनों का स्कोर 3-3 है।

बायर्न म्यूनिख ने ड्रिसेन और एबरल का अनुबंध जून 2029 तक बढ़ाया

बर्लिन, एजेंसी । बायर्न म्यूनिख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जान-क्रिश्चियन ड्रिसेन और स्पोर्टिंग बोर्ड मेंबर मैक्स एबरल का अनुबंध जून 2029 तक बढ़ा दिया है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले को बायर्न के सुपरवाइजरी बोर्ड ने मंगलवार को एक बैठक में मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद ड्रिसेन और एबरल का 2027 में समाप्त होने वाला कार्यकाल 2 साल बढ़ गया। ड्रिसेन 2013 में

मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर बायर्न में शामिल हुए थे और एक साल बाद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। वह मई 2023 से सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। अनुबंध बढ़ाए जाने के बाद ड्रिसेन ने कहा, 'मैं सुपरवाइजरी बोर्ड को उनके भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहते हैं कि एफसी बायर्न शीर्ष क्लब बना रहे जिस पर हम सभी को गर्व है। यही हमें प्रेरित करता है। हमने अभी भी बहुत योजनाएं बनाई हैं। ' 52 साल के एबरल, बोरूसिया मोनचेंग्लाडबैक और आरबी लीपजिग में प्रबंधन में काम करने के बाद मार्च 2024 में स्पोर्टिंग बोर्ड मेंबर के तौर पर बायर्न लौटे। वह छह साल की उम्र में बायर्न में शामिल हुए, यूथ सिस्टम में आगे बढ़े और बाद में क्लब के लिए अपना पेशेवर डेब्यू किया। एबरल ने कहा, 'जब से मैं यूथ टीमों में था, तब से एफसी बायर्न मेरे दिल के करीब रहा है। सुपरवाइजरी बोर्ड का भरोसा एक कीमती निशानी है और मैं इससे बहुत खुश हूं। ' सुपरवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हर्बर्ट हैनर ने कहा कि स्थिरता जरूरी है, स्थिरता ताकत देती है। हमें क्लब को सबसे ऊंचे स्तर पर लगातार विकसित करने के लिए हमें दोनों की जरूरत है। बायर्न यूरोप के शीर्ष क्लबों में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। हैनर ने कहा, ड्रेसेन, एबरल और मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव रूवेन कैस्पर का मैनेजमेंट बोर्ड क्लब को पिच पर और पिच के बाहर आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में था। जुलाई 2024 से बायर्न के मैनेजमेंट बोर्ड में तीन सदस्य हैं। इस स्ट्रक्चर का मकसद समन्वय बनाते हुए जल्दी फैसले लेने में मदद करना है।

विमेंस एशिया कप

पहली बार खेल रही इंडोनेशिया ने किया टीम का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। महिला एशिया कप 2026 का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में होना है। इंडोनेशिया की महिला टीम ने पहली बार टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले इंडोनेशिया ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान करने वाली इंडोनेशिया आखिरी टीम है। टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। अनुभवी कप्तान नंदा सकारिनी टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि वेलिक के साथ मिलकर बेहतरीन बॉलिंग ग्रुप में शामिल होंगी। टीम में आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की स्टार खिलाड़ी वेसिका रत्ना देवी, पुत्री सुवानदेवी और सांग मेयरपिरानी शामिल हैं। देसी वुलंडारी, ली कियाओ

और नी काडेक एरियानी भी टीम का हिस्सा हैं। इंडोनेशियाई टीम का क्वालीफिकेशन कैंपेन बहुत अच्छा रहा, वे थाईलैंड से हारने से पहले सेमीफाइनल तक पहुंचीं, और तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में हांगकांग, चीन से हार गईं। टीम ने जून में एसीसी विमेंस प्रीमियर कप के जरिए क्वालीफाई किया था। पूरे इवेंट में टीम के लिए सिर्फ 11 सदस्य खेले थे। सकारिनी क्वालीफाइंग में टीम की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थीं। इंडोनेशिया एशिया कप में ग्रुप बी का हिस्सा है। इस ग्रुप की अन्य तीन टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई हैं। एशिया कप कैंपेन में इंडोनेशिया का पहला मैच 31 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ है, इसके बाद वे 2 सितंबर को श्रीलंका और 4 सितंबर को यूएई का सामना करेंगे। पहली हार टूर्नामेंट में उतरी इंडोनेशिया के प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी। महिला एशिया कप के लिए इंडोनेशिया की टीमः नंदा सकारिनी (कप्तान), काडेक विंडा प्रास्तिनी, रहमावती पंगेस्टुटी, वेसिका रत्ना देवी, राडा रानी, ??देसी वुलंडारी, पुत्री सुवांडेवी, किसी सलीसा कासे, सांग मेप्रियानी, नी काडेक एरियानी, डेनीं बांगी, दारा अगुंग लक्ष्मी, ली कियाओ, मारिया कोराजोन वोम्बाकी, सोफिया वेलिक।

एंटीगुआ ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 30 रन से हराया, जोसुआ जेम्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच

एंटीगुआ, एजेंसी। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 का 16वां मुकाबला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्सल और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच खेला गया। एंटीगुआ ने बारबुडा को 30 रन से हरा दिया। बारबाडोस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एंटीगुआ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 155 रन बनाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा 56 रन कप्तान मोईन अली ने बनाए। 37 गेंदों पर खेली गई इस नाबाद पारी में मोईन ने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके अलावा, करिमा गोरे ने 27 और आमिर जंगू ने 26 रन बनाए। शमार स्प्रिंगर ने नाबाद 19 रन बनाए। बारबाडोस की तरफ से मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए।

ब्राजील के खिलाफ मैच से पहले विश्वकप खेलने वाली इस टीम से होगा भारत का सामना

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्राजील के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को 2026 फीफा विश्व कप में खेल चुकी पनामा से भिड़ेगी। पनामा फीफा रैंकिंग में 44वें स्थान पर है। यह मुकाबला खालिद जमील की टीम के लिए बड़ी चुनौती होने के साथ ब्राजील और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी मुकाबलों की तैयारी का अहम मौका होगा। भारतीय फुटबॉल टीम को ब्राजील के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले एक और बड़ी चुनौती मिल गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने मंगलवार को बताया कि भारत 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में पनामा की मेजबानी करेगा।

हालांकि, मैच किस मैदान पर खेला जाएगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पनामा 2026 फीफा विश्व कप में हिस्सा ले चुका है। ऐसे में ब्राजील से भिड़ने से ठीक पहले भारतीय टीम को एक और विश्व कप टीम के खिलाफ खुद को परखने का मौका मिलेगा।

फीफा रैंकिंग में 44वें नंबर पर है पनामा – पनामा इस समय फीफा की ताजा रैंकिंग में 44वें स्थान पर है। यानी वह दुनिया की शीर्ष-50 टीमों में शामिल है। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला इसलिए भी अहम होगा क्योंकि खालिद जमील की टीम को मजबूत अंतरराष्ट्रीय विपक्ष के खिलाफ अपनी तैयारी और स्तर को परखने का मौका मिलेगा।

विश्व कप टीमों के खिलाफ लगातार मुकाबले

पनामा के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए विश्व कप में खेलने वाली टीमों के खिलाफ प्रस्तावित चार मैचों की शुरुआत करेगा। इसके बाद भारतीय टीम 3 अक्टूबर को ब्राजील से भिड़ेगी। नवंबर में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दो मुकाबले खेलने हैं। दोनों टीमें 12 और 15 नवंबर को आमने-सामने होंगी। इस तरह भारतीय टीम को इस अवधि में उन टीमों के खिलाफ खेलने का शानदार मौका मिलेगा, जो 2026 विश्व कप का हिस्सा रही हैं।

बीबीएल में ड्राफ्ट सिस्टम खत्म, अब खिलाड़ियों को होगा और फायदा

सिडनी, एजेंसी। बिग बैश लीग (बीबीएल) अनुबंध से जुड़ी रोक गुरुवार से हटने के बाद इस टूर्नामेंट में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई और विदेशी खिलाड़ियों को अधिक राशि मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ महीनों की बातचीत और क्लबों से मिले फीडबैक के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार डब्ल्यूबीबीएल सीजन शुरू होने से छह सप्ताह पहले अनुबंध से जुड़े नए नियम घोषित कर दिए। नए नियमों के तहत विदेशी खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्टा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और बड़े घरेलू खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे देने के मकसद से जरूरी बड़े घरेलू खिलाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। क्लबों को विदेशी खिलाड़ियों को साइन न करने का विकल्प भी दिया गया है। यह रोक गुरुवार सुबह नौ बजे हट जाएगी और इससे बेन स्टोक्स और फिन एलन जैसे खिलाड़ियों के लिए बीबीएल क्लबों के साथ सीधे रिकॉर्ड अनुबंध साइन करने का रास्ता खुल जाएगा। साथ ही मेलबर्न रेनेगेड्स छोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लेग-स्पिनर एडम जम्पा को भी आखिरकार कोई क्लब मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के टी-20 विकेटकीपर जॉश इंग्लिश को भी सैद्धांतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है, हालांकि, टेस्ट ड्यूटी की वजह से हो सकता है कि वह आने वाले बीबीएल के किसी भी हिस्से के लिए उपलब्ध न हों, जिससे आने वाले सीजन के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने की उनकी संभावना बेहद कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बीबीएल खिलाड़ी और कई क्लब लंबे समय से विदेशी खिलाड़ियों के लिए बने 'ड्राफ्ट' सिस्टम से परेशान थे। इस सिस्टम की वजह से कई बार कम मशहूर विदेशी खिलाड़ियों को ड्राफ्ट के नियमों के कारण सबसे अच्छे लोकल खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा पैसे मिल जाते थे। डब्ल्यूबीबीएल में भी यही नियम लागू होंगे। विदेशी खिलाड़ियों के लिए कोई न्यूनतम संख्या तय नहीं होगी, 15 खिलाड़ियों की टीम में तीन 'मार्की' खिलाड़ी होंगे जिनका वेतन अधिक होगा। बीबीएल के बॉस एलिस्टर डॉब्सन ने बताया, 'खिलाड़ियों का बाजार लगातार बदल रहा है और बीबीएल और डब्ल्यूबीबीएल जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। क्लबों के पास अलग-अलग खिलाड़ियों की वैल्यू और उनके घरेलू या विदेशी होने के आधार पर अपना आकलन करने की आजादी होना जरूरी है, और आखिरकार बात यही है कि क्लबों को अपनी टीम को लेकर आजादी मिले। इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि हमारी लीग में बेहतरीन विदेशी खिलाड़ी आएंगे क्योंकि वे हर टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे।

न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है: रोजर फेडरर

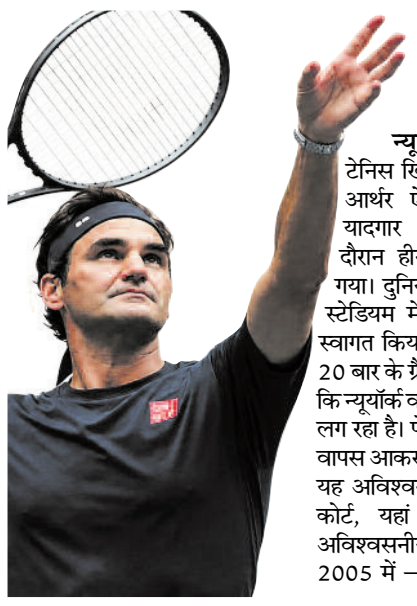

न्यूयॉर्क, एजेंसी। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का आर्थर ऐश स्टेडियम में एक यादगार एग्जिबिशन नाइट के दौरान हीरो जैसा स्वागत किया गया। दुनिया के सबसे बड़े टेनिस स्टेडियम में घुसते ही तालियों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने कहा कि न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फेडरर ने कहा, 'न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह अविश्वसनीय है। मेरे पास इस कोर्ट, यहां के फैंस, शहर की अविश्वसनीय यादें हैं। 2004, 2005 में – यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, यहां की जीतों के साथ न्यूयॉर्क के लिए मेरा प्यार। ' फेडरर ने कहा, 'मुझे पहले दिन से ही इस शहर और इस कोर्ट से प्यार हो गया था। ' पूर्व खिलाड़ी ने 2004-2008 तक लगातार पांच यूएस ओपन जीते और टूर्नामेंट और शहर के साथ अपने खास कनेक्शन के बारे में बात की।

स्विस खिलाड़ी ने आर्थर ऐश स्टेडियम के सेंटर कोर्ट पर अपनी पहली मौजूदगी को याद किया, जो 2001 में अगासी के खिलाफ थी। फेडरर वह मुकाबला सीधे सेटों में हार गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि सेंटर कोर्ट पर मेरा पहला मुकाबला आंद्रे के खिलाफ 2001 में था। उन्होंने मुझे 6-1, 6-2, 6-4 से हराया। मेरे पास कोई शॉट नहीं था। मैं ऐसा था, 'ठीक है, इतना आसान नहीं है, इतना तेज नहीं है, रोजर'। स्टेडियम के वीडियो बोर्ड पर एक्टर मैथ्यू मैककोनाघी का नैरेट किया हुआ एक हाइप वीडियो दिखाया गया, और फैशन आइकन एना विंटोर ने रॉडिक के खिलाफ फेडरर के एकल मैच से पहले सिक्का उछाला। सेरेना विलियम्स, फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे, कैस्पर रूड और एलेक्जेंड्रा एला समेत कई मौजूदा और पुराने टेनिस स्टार भी मौजूद थे। फेडरर की यूएस ओपन में वापसी उनके पोस्ट-प्लेइंग करियर में एक और बड़ी उपलब्धि से कुछ दिन पहले हुई है। इस महीने की शुरुआत में अपना 45वां जन्मदिन मनाने वाले स्विस खिलाड़ी को शनिवार, 29 अगस्त को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। आंद्रे अगासी ने कहा, 'यह कितना कूल है कि यह बंदा इस साल हॉल ऑफ फेम में जा रहा है? बहुत बढ़िया, रोजर। मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे कहना होगा – मुझे लगता है कि मैं पहला इंसान था जिसे पता चला कि वह हॉल ऑफ फेम में जाने वाला है। जब उसने अपना 19वां स्लैम जीता, तो मुझे लगा, 'हां, वह कर सकता है'। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि 20वां गैर-जरूरी (हंसते हुए) था। फिर भी, मैं सच में बहुत उत्साहित हूं क्योंकि इससे बाकी सभी लोग जो मुश्किल से अंदर जाने का तरीका ढूंढ पाए हैं, अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करते हैं। रॉडिक ने भी फेडरर के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए कहा, 'हमने बहुत खेला और उसने मुझे बहुत हराया। लेकिन हम हमेशा अपने करियर के बीच में दोस्ती बनाए रखने में कामयाब रहे और यह अब तक चली है और उम्मीद है कि हमेशा रहेगी। फेडरर ने 2022 में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया था। आखिरी बार फेडरर ने 2019 में यूएस ओपन खेला था।

कोलंबो टेस्ट में छा गए सोनल दिनूषा, जड़ा ऐतिहासिक शतक

बनाया सनत जयसूर्या- महेला जयवर्धने वाला महारिकॉर्ड

श्रीलंका बनाम भारत

कोलंबो, एजेंसी। भारत के खिलाफ श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनूषा का शानदार प्रदर्शन जारी है. 25 साल के दिनूषा ने कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. दिनूषा ने इस मुकाबले में 103 रनों की पारी खेली. उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका ने 290 रनों का स्कोर बनाया, हालांकि दिनूषा अपनी टीम को फॉलोऑन से नहीं बचा सके, जिसके लिए श्रीलंका को 304 रनों का स्कोर बनाना था. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 503-9 रन बनाकर घोषति की. कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में सोनल दिनूषा ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. चौथे दिन यानी बुधवार (26 अगस्त) को दिनूषा ने 147 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यह इस सीरीज में दिनूषा का दूसरा शतक है. इससे पहले गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने एक पारी में 100 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 84 रन जड़े थे. अब कोलंबो में शतक के साथ उनका मौजूदा सीरीज में स्कोर 100, 84 और 103 हो गया है.

जयसूर्या और जयवर्द्धने वाले क्लब में एंट्री – सोनल दिनूषा अब भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाजों की खास सूची में शामिल हो गए हैं. इस सूची में सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्द्धने जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं. 25 साल के सोनल भारतीय ऑफ स्पनिर सारांश जैन की गेंद पर आउट हुए, उनको केएल राहुल ने आउट किया.

भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज

- अरविंद डी सिल्वा – 3 बार
- कुमार संगकारा – 3 बार
- सनथ जयसूर्या – 2 बार
- महेला जयवर्धने – 2 बार
- थरंगा परानाविताना – 2 बार
- एंजेलो मैथ्यूज – 2 बार
- सोनल दिनूषा – 2 बार

प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पूरा किया शतक दिनूषा

दिनूषा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गें द पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. गें द छोटी और ऑ फ स्टंप के बाहर थी, जिस पर उन्हों ने शानदार पुल शॉट खेला. गें द हवा में जरूर गई , ले किन आसानी से इनफील्ड को पार करते हुए बाउं ड्री के बाहर पहुंच गई . शतक पू रा होने के बाद दिनू षा ने बल्ले को चू मा, हेलमेट उतारा और दर्श कों का अभिवादन स्वीकार किया. खास बात यह रही कि इस सीरीज में उनकी यह एक और लगभग बे दाग पारी रही. दोनों टीमों में दे वदा पडिकल ने उनसे ज्यादा रन बनाए हैं , ले किन दिनू षा की बल्ले बाजी पर नियं त्रण ने उन्हें इस सीरीज के सबसे प्रभावशाली बल्ले बाजों में शामिल कर दिया है .

भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में कई शतक

- 2 – एवर्टन वीक्स (वेस्टइंडीज, 1948)
- 2 – गारफील्ड सोबर्स (वेस्टइंडीज, 1958)
- 2 – ज़हीर अब्बास (पाकिस्तान, 1978)
- 2 – दुलीप मेंडिस (श्रीलंका, 1982)
- 2 – रॉबिन स्मिथ (इंग्लैंड, 1990)
- 2 – गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका, 1996)
- 2 – जेसी राइडर (न्यूजीलैंड, 2009)
- 2 – सोनल दिनुषा (श्रीलंका, 2026)

श्रीलंका फॉलोऑन के बाद भारत से 16 रन आगे, स्कोर-229/6: पसिंदु ने 92 रन बनाए; सुथार को दो विकेट, बारिश से मैच बाधित

भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में फॉलोऑन खेल रही श्रीलंका ने दूसरी पारी में 229/6 रन बनाए हैं। टीम ने भारत की पहली पारी के स्कोर से 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। सोनल दिनूषा 7 और केशरा नुवनथा 3 रन पर नाबाद हैं। चौथे दिन बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। पसिंदु सोरियाबंडारा 92 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मानव सुथार ने पवेलियन भेजा। सुथार ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी 23 रन पर आउट किया। इससे पहले निरोशन डिकवेला 6 रन पर सारांश जैन, कमिंदु मेंडिस 55 रन पर प्रसिद्ध कृष्णा, कमिल मिशारा 32 रन पर रवींद्र जडेजा और लाहिरू उदारा 3 रन पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर आउट हुए।

संक्षिप्त समाचार

फिजी के मंदिरों में गूंज रहे भजन, सदियों की भारतीय परंपरा पर प्रवासियों को गर्व, विदेशी भी ले रहे प्रेरणा

सुवा, एजेंसी। भारत से हजारों किमी दूर प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप-राष्ट्र फिजी में भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूरों के साथ वहां पहुंची थीं। श्रावण माह में यहां के मंदिर और सामुदायिक भवन में भक्ति-गीतों से सराबोर रहे। अगस्त में भजन जैमिंग 2026 कार्यक्रम युवाओं के लिए खास उत्साह का केंद्र रहा। यहां के राम मंदिर में अभी से रामलीला की तैयारियां भी की जाने लगी हैं। घरों में रामायण बजती है। सदियों की भारतीय परंपरा पर प्रवासियों को बेहद गर्व है और विदेशी भी परंपराओं के पालन की प्रेरणा ले रहे हैं। यहां के प्रमुख अखबार फिजी सन ने के मुताबिक, भजन जैमिंग कार्यक्रम में फिजी स्थित भारतीय-मूल के युवाओं ने पारंपरिक भजनों को समकालीन संगीत अंदाज में पेश किया। कार्यक्रम में बंदिश ग्रुप, सुकून ग्रुप और हनुमान चालीसा परिवार जैसी स्थानीय भजन-मंडलियों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक के भारतीय छात्र संगठन ने भी प्रस्तुति दी। फिजी में बॉलीवुड मुख्य रूप से फिल्म शूटिंग, रेडियो शो, कंसर्ट्स और स्थानीय इंडो-फिजीयन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है।

समृद्ध महासागर का हिस्सा- मिस्र के रेगिस्तान में कभी तैरती थीं विशाल शार्क मछलियां, क्रमिक रूप से हुआ विकास

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। मिस्र का रेगिस्तान करोड़ों साल पहले (लगभग 14.5 से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व) एक विशाल और समृद्ध महासागर का हिस्सा था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित अबू-तरतूर पठार पर शार्क के प्राचीन जीवाश्म और दांतों की खोज की है, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह सूखा क्षेत्र कभी समुद्री जीवों और विभिन्न प्रजातियों की शार्क का गढ़ था। मिस्र में प्राचीन शार्क के जीवाश्मों की खोज से जु?ी यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका %क्रिटेशियस रिसर्च% में प्रकाशित हुई है।मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान की चट्टानों से काहिरा विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी तारेक यासीन ने सात अलग-अलग शार्क प्रजातियों के दुर्लभ जीवाश्मों और शार्क के दांतों का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मिलने वाले दांतों की आकृतियां अलग-अलग हैं। कुछ सुई जैसी नुकीली हैं तो कुछ चौड़ी और आरी के आकार की हैं, जो शिकार के अनुकूल थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्राचीन काल में यहां गहरी समुद्री धाराएं चलती थीं जो पानी की सतह पर पोषक तत्व लाती थीं। इससे प्लवक और छोटी मछलियों का विकास हुआ, जिस कारण यह पूरा क्षेत्र शार्क जैसे बड़े शिकारियों के लिए आदर्श स्थान था।

सूडान में 59 हजार मौतों के बाद अमेरिका सख्त, ह्व से पूरे देश में हथियार बैन की मांग; बढ़ेगा दबाव

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। सूडान में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरब और अफ्रीकी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार मासाद बोलोस ने सोमवार को कहा कि प्रतिबंधों के जरिए युद्ध में शामिल दोनों पक्षों पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ाया जा सकता है। सूडान में चल रही इस लड़ाई में अब तक कम से कम 59 हजार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। देश के कई हिस्से अकाल की चपेट में हैं। बोलोस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि सूडानी सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को मिल रहा वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक समर्थन संघर्ष को लंबा खींच रहा है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन मिस्र सूडान की सेना का खुलकर समर्थन करता रहा है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात पर ह्व विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने ऋस्स्न को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया है। इन आरोपों से इनकार करता रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें सूडान के पूरे क्षेत्र में हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। मौजूदा प्रतिबंध मुख्य रूप से पश्चिमी दारफुर क्षेत्र तक सीमित है। प्रस्ताव में सूडान में सक्रिय सभी पक्षों पर प्रतिबंध लागू करने और ड्रोन व उनसे जुड़ी तकनीक को भी हथियार प्रतिबंध के दायरे में रखने की बात कही गई है। अमेरिकी प्रस्ताव में सभी देशों से सूडान के युद्धरत पक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य, वित्तीय और लॉजिस्टिक मदद बंद करने की मांग की गई है। अमेरिका का कहना है कि बाहरी सहायता युद्ध को जारी रखने और शांति प्रयासों को कमजोर करने में भूमिका निभा रही है।

अमेरिका में एआई की वजह से नहीं जाएगी शिक्षकों की नौकरी: शिक्षा मंत्री बोलीं- मशीन नहीं ले सकता इंसान की जगह

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय और स्पष्ट सीमाएं तय होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ढ्ढ को कभी भी शिक्षकों के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मैकमोहन ने कहा कि ढ्ढ अब शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक चाहे जितनी विकसित हो जाए, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच मानवीय संवाद की जगह नहीं ले सकती।

एआई को अपनाना जरूरी, लेकिन सुरक्षा उपाय भी हों : मैकमोहन ने कहा कि सरकार ने फिलहाल एआई को रेगुलेट करने के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की है, लेकिन वह शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि ढ्ढ आ चुका है और स्कूलों को इससे दूरी बनाने के बजाय इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। उन्होंने ऑस्टिन, टेक्सास के अल्फा स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने वहां ढ्ढ को वास्तविक कक्षा में काम करते हुए देखा है। उनके मुताबिक, इस तकनीक को अपनाने के साथ कुछ नियम और सुरक्षा सीमाएं तय करना भी जरूरी है, ताकि इसका इस्तेमाल छात्रों के हित में हो।

शिक्षक की जगह नहीं ले सकता एआई : अमेरिकी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई का इस्तेमाल शिक्षक के विकल्प के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच प्रत्यक्ष मानवीय संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। मैकमोहन के मुताबिक, तकनीक बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन शिक्षा केवल जानकारी हासिल करने का नाम नहीं है। कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन, संवाद और बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कमजोर छात्रों से लेकर तेज छात्रों तक : मैकमोहन ने एआई के संभावित फायदों को गिनाते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए एक व्यक्तिगत ट्यूटर की तरह काम कर सकता है। जो छात्र किसी विषय में पीछे रह गए हैं, वे ढ्ढ की मदद से पाठ दोबारा समझ सकते हैं और अपनी गति से अभ्यास कर सकते हैं। वहीं, जो छात्र अपनी कक्षा के स्तर से आगे हैं, उनके लिए ढ्ढ ज्यादा उन्नत सामग्री और चुनौतीपूर्ण पाठ उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह छात्रों के लिए एक बेहद उपयोगी अवसर साबित हो सकती है।

शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी : मैकमोहन ने ट्रंप प्रशासन की शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की योजना पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि कई जिम्मेदारियां संघीय सरकार से वापस राज्यों को दी जाएं। मैकमोहन के मुताबिक, ट्रंप का मानना है कि दशकों तक भारी खर्च के बावजूद अमेरिकी छात्रों के परीक्षा परिणाम लगातार कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे कहा था कि देश अपने बच्चों के लिए अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाया है और अब इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है।

3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च, फिर भी टेस्ट स्कोर में गिरावट : मैकमोहन ने कहा कि अमेरिकी शिक्षा विभाग 1980 में अस्तित्व में आया और तब से शिक्षा पर 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद छात्रों के टेस्ट स्कोर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने इसी आधार पर तर्क दिया कि मौजूदा संघीय शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। उनका कहना है कि शिक्षा से जुड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां राज्यों को सौंपने से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और स्कूलों की जरूरत के मुताबिक नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। मैकमोहन ने कहा कि शिक्षा विभाग को पूरी तरह खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। इसलिए प्रशासन फिलहाल यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विभाग की कुछ जिम्मेदारियां दूसरी संघीय एजेंसियां ज्यादा प्रभावी ढंग से संभाल सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन विभिन्न विभागों के बीच अंतर-एजेंसी समझौते कर रहा है और कुछ कार्यक्रमों तथा जिम्मेदारियों को दूसरी एजेंसियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैकमोहन के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य कांग्रेस के सामने यह साबित करना है कि शिक्षा से जुड़े कुछ काम शिक्षा विभाग के बाहर भी प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं।

राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की तैयारी : मैकमोहन ने कहा कि शिक्षा को राज्यों के स्तर पर वापस ले जाना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका तर्क है कि स्थानीय और राज्य सरकारें अपने छात्रों की जरूरतों को संघीय सरकार की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को मुख्य रूप से कांग्रेस द्वारा स्वीकृत धनराशि को आगे पहुंचाने वाली संस्था के रूप में भी वर्णित किया। उनके मुताबिक, विभाग के कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के गठन से पहले दूसरी संघीय एजेंसियों के माध्यम से संचालित होते थे।

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से राहत- पोस्टल बैलेट से मतदान संबंधी आदेश को मिली मंजूरी, मध्यावधि चुनाव पर क्या असर

वाशिंगटन, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतपत्र से मतदान को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनका प्रशासन आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले इसे कितना लागू कर पाएगा। इस निर्णय से अतिरिक्त अदालती चुनौतियों की संभावना बनी हुई है, जो ट्रंप के आदेश को और धीमा कर सकती हैं। अमेरिकी डाक विभाग ने पिछले सप्ताह आदेश को लागू करने की अपनी योजना बताई थी। दरअसल, कुछ राज्यों में कुछ ही हफ्तों में मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे बड़े बदलाव लागू करने के लिए समय कम है। ट्रंप लंबे समय से डाक मतपत्र मतदान को धोखाधड़ी का जरिया बताते रहे हैं, हालांकि इसके विपरीत मजबूत सबूत मौजूद हैं। उन्होंने स्वयं भी इस मतदान पद्धति का उपयोग किया है। न्याय विभाग ने उच्च न्यायालय से मध्यावधि चुनावों से पहले परिवर्तनों को लागू करने की अनुमति देने के लिए एक आपातकालीन अपील दायर की थी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर मार्च में हस्ताक्षर किए गए थे। यह उनके प्रशासन से योग्य मतदाताओं की सूची बनाने और अमेरिकी डाक विभाग को केवल उन सूचियों में शामिल लोगों को डाक मतपत्र वितरित करने का आदेश देता है।

आदेश को चुनौती और अदालती निर्णय : 23 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के डेमोक्रेटिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान राज्यों और कांग्रेस को चुनाव कराने की शक्ति देता है। ट्रंप के बदलावों से अराजकता और पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग हो सकता है। राज्यों के वकीलों ने लिखा, इस गिरावट के चुनावों के इतने करीब ऐसे परिवर्तनकारी बदलावों को प्रभावी होने के परिणाम अत्यधिक होंगे।% मैसाचुसेट्स में एक न्यायाधीश ने उन राज्यों में मध्यावधि चुनावों के लिए योजना को रोक दिया था। एक अपील अदालत ने उनके फैसले को बरकरार रखा। बाद में उन्होंने इसे देशव्यापी रूप से रोकने का दूसरा आदेश दिया। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई के अंत में प्रक्रियात्मक आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों ने बहुत जल्दी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने वाशिंगटन से आए एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया, जहां एक न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

ईरान में युद्ध और महंगाई के बीच युवाओं का सुकून भी छिना, दर्जनों कैफे सील, क्या चाहती है हुकूमत

लैली निकूनाजार/येगाने तोरबाती, तेहरान, एजेंसी। युद्ध के साये, आसमान छूती महंगाई और रोजगार के घटते अवसरों के बीच ईरान की युवा पीढ़ी के पास सामान्य जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही सस्ता जरिया बचा था-शाम के वक्त दोस्तों के साथ किसी कॉफी शॉप में बैठकर थोड़ा वक्त सुकून से काटना। लेकिन फुटपाथ में कुर्सियों पर पसरे युवा, सिगरेट का धुआं, बेपरवाह गपशप और कभी-कभार छिपाकर बीयर पीने (जिसकी सजा देश में कोड़े हैं), वाले ये दृश्य कट्टरपंथी हुकूमत को खामोश बगावत नजर आने लगे। नतीजा, पुलिस-प्रशासन कैफे बंद कराने लगा।

राजधानी तेहरान समेत देश के कई शहरों में हाल में दर्जनों कैफे, रेस्टोरेंट और बुटीक सील किए?गए?हैं। वैसे तो वजह यही बताई गई कि अनिवार्य हिजाब कानून और इस्लामी मूल्यों की अनदेखी हो रही है। लेकिन तेहरान के कैफे मालिक आमिर का कहना है कि यह हुकूमत की बेचैनी और युद्ध से थके समाज को नियंत्रित करने की कोशिश है। आमिर कहते हैं, हम खुद को यही तसल्ली देते हैं कि यह सिर्फ एक लहर है। ईरान के कॉफी शॉप कल्चर पर किताब लिखने वाली हालेह मीर मीरी के अनुसार, इसमें युवा जिंदगी जीने के वैकल्पिक रास्ते तलाशते हैं। तेहरान की आर्टिस्ट मोना कहती हैं, कैफे छोटे होने से लोग फुटपाथ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि यह प्रदर्शन की तैयारी है। ईरान में कैफे के आसपास इस तरह युवाओं की भीड़ जुटने को सरकार संभावित प्रदर्शन से जोड़कर देख रही है। यही नहीं, सार्वजनिक जगह पर हावी होने की कोशिश में भी सरकार कड़े कदम उठा रही है। क्योंकि युद्ध की अनिश्चितता के बीच हुकूमत अपने समर्थन में रैलियां निकाल रही है। ऐसे माहौल में कैफे का यह आजाद माहौल सरकारी नैरेटिव को सीधी चुनौती देता है। ईरान में इन दिनों एक पुराना सामाजिक और सांस्कृतिक टकराव फिर से भड़क उठा है। ईरान की राजधानी तेहरान और ऐतिहासिक शहर शिराज की सड़कों पर आजकल एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है।

ट्रंप का बड़ा खुलासा- दो हफ्ते में अमेरिका आएंगे शी जिनपिंग, व्हाइट हाउस में बन रहा 'चीन जैसा' ग्रेट हॉल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खुलासा किया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब दो हफ्ते में अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने यह घोषणा व्हाइट हाउस के पास निर्माणाधीन नए बॉलरूम और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हुए की। उन्होंने परियोजना की तुलना चीन के 'ग्रेट हॉल' से की और साथ ही नए हेलीपोर्ट को भी वर्षों से लंबित जरूरत बताया। हालांकि, शी की यात्रा को लेकर अभी चीन या व्हाइट हाउस की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम और अन्य विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रंप ने यह जानकारी व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित 'बैक-टू-स्कूल' कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान दी। हालांकि, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ होने वाली बातचीत की तारीख, कार्यक्रम और यात्रा से जुड़ी अन्य

जानकारियां साझा नहीं कीं। ट्रंप ने कहा,राष्ट्रपति शी दो हफ्ते में आ रहे हैं। मैं दो महीने पहले चीन गया था और हमने चीन का 'ग्रेट हॉल' देखा था। अब अमेरिका में भी हमारा अपना 'ग्रेट हॉल' होगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है।÷

ट्रंप ने व्हाइट हाउस परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों से इस प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स को जोड़ते हुए बताया कि परियोजना में एक भव्य बॉलरूम के साथ-साथ एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी शामिल होगा। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हम वहां एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और एक बॉलरूम बना रहे हैं, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बेहतरीन होगा। शिक्षा पर अपनी बात रखने के बाद राष्ट्रपति एक बार फिर निर्माण कार्य की चर्चा पर लौट आए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों और उनके परिवारों को अपने साथ निर्माण स्थल देखने के लिए आमंत्रित किया। ट्रंप ने कहा, आप ठीक बगल में व्हाइट हाउस के पास बन रही शानदार इमारत देखेंगे। वही बॉलरूम और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स होगा। यह अद्भुत है। उन्होंने बताया कि प्रशासन व्हाइट हाउस में एक नया हेलीपोर्ट भी बना रहा है। ट्रंप के मुताबिक, पहले हेलीकॉप्टरों को घास पर उतरना पड़ता था, जिससे गीले मौसम में परेशानी और सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा होते थे। ट्रंप ने कहा, हम एक सुंदर हेलीपोर्ट बना रहे हैं, जिसकी मांग कई वर्षों से की जा रही थी। हेलीकॉप्टर को गीली घास पर उतरना पड़ता था, जो खराब और खतरनाक था।%रोज गार्डन में जुटे बच्चों को निर्माण कार्य दिखाने को लेकर ट्रंप खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने निर्माण स्थल से आने वाली आवाजों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें निर्माण कार्य की आवाज पसंद है। ट्रंप ने कहा, मुझे निर्माण कार्य की आवाज बहुत पसंद है। जब मैं बाहर वह शोर-शराबा सुनता हूं।

चीन में भारतीय फैशन का जलवा, कुर्ते से साड़ी तक का बढ़ा क्रेज; क्यों पसंद आ रहा देसी अंदाज

शंघाई/बीजिंग, एजेंसी। पश्चिमी देशों और रूस में भारतीय एथनिक फैशन की पहचान बनने के बाद अब चीन जैसे पड़ोसी देश में भी भारतीय पहनावे का नया क्रेज देखा जा रहा है। बीजिंग से शंघाई तक चीनी युवा सलवार-कुर्ती और इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन आउटफिट्स पहनकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो महिलाओं को भी साड़ी में देखा जा रहा है। लोग पलिनन के लंबे-छोटे कुर्तों को डेनिम जींस, ट्राउजर और वाइट स्नीकर्स के साथ पेयर करके मिनिमलिस्टिक लुक अपना रहे हैं। चीन के उमस भरे मौसम में सांस लेने योग्य भारतीय कॉटन, खादी और चंदेरी फैब्रिक की भारी मांग है। श्याओहांगशू (रेड बुक) ट्रेंड्स डाटा के मुताबिक, शंघाई के प्रसिद्ध अंफु रोड और उहांग रोड जैसे स्ट्रीट-फैशन हब्स पर कुर्ता-डेनिम लुक छाया हुआ है। शैनक्सी

साउथ रोड के मल्टी-ब्रांड बुटीक में भी भारतीय फैब्रिक हावी है। वहीं, बीजिंग के सानलीतुन स्ट्रीट जोन और ताइगू ली एवेन्यू पर युवा कुर्तों को डेनिम व स्नीकर्स के साथ स्टाइल कर रहे हैं। चीनी अखबार चायना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, फैशन शो और बीटूबी मीट्स में लेबलहुड की संस्थापक ताशा लियू ने इस फ्यूजन ट्रेंड को बढ़ावा दिया, जिसके बाद ताओबाओ और श्याओहांगशू के सेलर नेटवर्क ने भारी मात्रा में बल्क ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं।

फैशन शो और बीटूबी मीट्स के दौरान चीनी रिटेलर्स ने भारतीय टेक्सटाइल और फ्यूजन वियर के लिए 12 लाख डॉलर (10 करोड़ रुपये) के शुरुआती सप्लाई ऑर्डर्स दिए हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। 6 माह के दौरान चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (ताओबाओ व टीमाल) पर इंडियन स्टाइल एथनिक कुर्ती और मसाला चाय मिक्स की बिक्री 45त्न तक बढ़ गई है।

चीन के मेट्रो शहरों (शंघाई, बीजिंग और चेंगदू) में इन दिनों भारतीय लाइफस्टाइल और एथनिक फैशन का एक अनोखा उभार देखने को मिल रहा है। चीन के सबसे बड़े लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म श्याओहांगशू पर भारतीय पहनावे, इंडो-फ्यूजन स्टाइलिंग और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के ट्रेंड्स की बाढ़ आ गई है। खास तौर पर साड़ियों का भी चलन खूब देखने को मिल रहा है।

रेड कार्पेट और फैशन शो में लंबी कतारें = शंघाई के अंतरराष्ट्रीय फैशन कॉरिडोर में ईस्ट-मीट्स-वेस्ट फ्यूजन शो और बीजिंग कल्चरल एक्सपो हुआ, जिसमें भारतीय एथनिक व इंडो-वेस्टर्न डिजाइनों का प्रदर्शन हुआ। चीनी फैशन इन्फ्लुएंसर ली जियाओयान शंघाई की प्रसिद्ध स्टाइलिस्ट चेन वेई ने भारतीय चंदेरी, बनारसी और ब्लॉक-प्रिंट सिल्क के साथ आधुनिक कट-आउट्स का प्रयोग कर रेड कार्पेट पर धूम मचाई। इस 3 दिनी शो में 15,000 से अधिक दर्शक व खरीदार मौजूद रहे।

खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो पर सख्ती; टिकटॉक समेत इन प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी, क्या कहा

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन की सरकार ने सोमवार को टिकटॉक और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले वीडियो हटाएं। सरकार ने इन वीडियो को वायरल होने से रोकने को कहा है। यह कदम एक सड़क हादसे में दो पुलिस अधिकारियों और पांच युवकों की मौत के बाद उठाया गया है। हादसे के समय एक कार सड़क की गलत दिशा में जा रही थी। शनिवार को अधिकारी मैथ्यू ब्लेड्स और टॉम क्लॉ की मौत हो गई। उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड में एक वोक्सवैगन कार सड़क पर गलत दिशा में जा रही थी। इसी दौरान वह पुलिस अधिकारियों की गाड़ी से टकरा गई। कार में सवार पांच लोगों की भी मौके पर मौत हो गई। इनमें तीन लड़के थे। उनकी उम्र 17 और 18 साल थी। दो अन्य पुरुष थे। दोनों की उम्र 23 साल थी।

खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो क्यों चिंता बढ़ा रहे हैं : यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब सोशल मीडिया में उन वायरल वीडियो को लेकर चिंता बढ़ी है, जिनमें लोग खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। ऐसे वीडियो खुद गाड़ी चलाने वाले लोग पोस्ट करते हैं। कई बार गाड़ी में बैठे दूसरे लोग भी इन्हें सोशल मीडिया पर डालते हैं। ब्रिटिश मीडिया की खबरों के मुताबिक, शनिवार को वोक्सवैगन कार में मारे गए लोगों में से एक ने पहले भी ऐसा वीडियो पोस्ट किया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ल्यूक पोलार्ड ने कहा कि सरकार ने टिकटॉक और ऐसी दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों से ऐसे खराब कंटेंट को हटाने और अपनी कार्रवाई तेज करने को कहा है। उन्होंने बीबीसी से कहा, हमने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात की है, जहां सड़कों पर इस तरह के खतरनाक व्यवहार का जश्न मनाने वाला कंटेंट डाला जा रहा है। हमने उनसे ऐसा कंटेंट हटाने को कहा है।

पोलार्ड ने आगे कहा, इन कंपनियों ने कुछ नियमों का विरोध करते हुए कहा था कि वे खुद अपने प्लेटफॉर्म की निगरानी कर सकती हैं। अब यह दिखाने का सही मौका है कि वे ऐसा कर सकती हैं। सड़कों पर खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा देने वाला कंटेंट हटाया जाए।

प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के कार्यालय ने कहा कि वीडियो और मनोरंजन के लिए खतरनाक ड्राइविंग को बढ़ावा देना बेहद शर्मनाक है। कार्यालय ने कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ब्रिटेन के मीडिया नियामक को सरकार का पूरा समर्थन है। टिकटॉक ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, कंपनी ने कहा कि उसकी नीतियों के तहत ऐसे कंटेंट पर सख्त रोक है, जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकता है। पुलिस ने बताया कि जिस कार से यह जानलेवा हादसा हुआ, उस पर नकली नंबर प्लेट लगी थी। इसका इस्तेमाल पुलिस से बचने के लिए किया गया था। पुलिस ने कहा कि हादसे से पहले संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों के मामले में सोमवार को 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें हथियार रखने का मामला भी शामिल है। एक अलग मामले में, आयरलैंड के काउंटी किल्डेयर में पिछले हफ्ते चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। उनकी कार को राजमार्ग पर गलत दिशा में जा रही दूसरी कार ने टक्कर मार दी।

हेगसेथ बोले- जरूरत पड़ी तो ईरान पर मिसाइल से हमला; सख्ती पर इस्राइली पीएम नेतन्याहू क्या बोले

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक और सैन्य दबाव को एक साथ तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने होर्मुज जलडमरूमध्य समेत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा है, जबकि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के जरिए ईरान के तेल, वित्तीय नेटवर्क और प्रतिबंधों से बचने वाले तंत्र को निशाना बनाने की घोषणा की है। दूसरी ओर, ईरान ने संकट से निपटने का भरोसा जताया है और इस्राइल ने अमेरिकी कदमों का समर्थन किया है। इससे तेहरान पर आर्थिक दबाव के साथ संभावित सैन्य टकराव का जोखिम भी बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर दो मोर्चों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है एक तरफ आर्थिक घेराबंदी और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई का खुला विकल्प।

होर्मुज में भी सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं : विस्कॉन्सिन के ओशकोश दौरे के दौरान हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना को बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या फिलहाल सैन्य हमलों का विकल्प रोक दिया गया है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं है। हेगसेथ के मुताबिक, अगर ईरान अमेरिकी सेना से टकराता है या ऐसी कार्रवाई करता है जिसे वॉशिंगटन सीमा पार करना मानता है, तो अमेरिका जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल आर्थिक दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर होर्मुज जलडमरूमध्य या ईरान के आसपास किसी भी इलाके में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है।

अमेरिका का दावा-होर्मुज पर मजबूत पकड़ : हेगसेथ ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करने की क्षमता रखती है। उनके अनुसार, ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है और तेहरान यह भी समझता है कि जलडमरूमध्य में

अमेरिकी सैन्य क्षमता उसके मुकाबले काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इस क्षेत्र से व्यापार और तेल की आवाजाही को प्रभावित करने की कुछ क्षमता जरूर है, लेकिन अमेरिका के पास समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने की बेहतर क्षमता मौजूद है। उनका दावा है कि इसी वजह से तेल का प्रवाह जारी रखा जा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान के दबाव को सीमित किया जा सकता है।

ईरानी नौसेना और मिसाइल क्षमता को नुकसान का दावा : हेगसेथ ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की नौसेना, रडार और मिसाइल प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि ईरान के पास अब भी कुछ सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक, ईरान की मौजूदा सैन्य क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है। इसी आधार पर वॉशिंगटन का मानना है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और तेल की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति को जारी रख सकता है।

आर्थिक दबाव के साथ परमाणु वार्ता का लक्ष्य : हेगसेथ ने कहा कि लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी रणनीति का मकसद तेहरान की आर्थिक क्षमता को इतना कमजोर करना है कि उसके सामने बातचीत के अलावा विकल्प सीमित रह जाएं। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव और सैन्य विकल्प दोनों एक-दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। वॉशिंगटन फिलहाल आर्थिक हथियार को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना खुली रखी गई है।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट से ईरान की वित्तीय घेराबंदी : अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने की घोषणा की। उनके मुताबिक, इस अभियान का लक्ष्य दुनियाभर में ईरान के वित्तीय संपर्कों को तोड़ना और उन सभी आय स्रोतों पर कार्रवाई करना है जो ईरानी सरकार तथा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। अमेरिका ने इस अभियान के तहत करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है। इनमें ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल कारोबार से कथित रूप से जुड़े लोग और संस्थाएं शामिल हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हिमाचल में भूकंप, किचन में रखे वर्तन गिरे, सुबह-सुबह लगे झटके लोग घरों से निकले

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल की राजधानी शिमला सहित आस पास के शहरों में आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया। घरों की किचन में रखे वर्तन गिरने लगे। जब तक लोग समझ पाते तब तक झटके लगने लगे। लोग डर के चलते घरों से बाहर निकले तब पता चला कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। सुबह 5 बजकर 46 मिनट और 50 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। इसका केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे जुब्बल-कोटखाई की तरफ था। यह झटका लगभग तीन सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके दौरान धरती डोलने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, उस समय कई लोग नींद में थे, जिस वजह से उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तेज झटका लगने की जानकारी साझा की। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के कई अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके अनुभव किए गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्यों में आता है, जिसमें शिमला और मंडी जैसे जिले जोन-4 और जोन-5 के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर 5.0 से कम तीव्रता वाले भूकंपों से बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना कम होती है। इससे पहले हाल ही में चंबा और कांगड़ा जिलों में भी भूकंप के झटके दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

गोवा कैबिनेट का ऐतिहासिक कदम : गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा का प्रस्ताव

पणजी (एजेंसी)। गोवा कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परवर्तन निषेध विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जबरन, दबाव, लालच, धोखाधड़ी या शादी के मकसद से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है। प्रस्तावित कानून के तहत इसतरह के मामलों में दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। विधेयक प्रावधान करता है कि यदि कोई शादी केवल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई हो, तब उस शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। धर्मांतरण में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यदि धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तब यह सजा 5 से 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ सकती है। मुख्य सचिव वी. कंडावेलू ने इस कानून के उद्देश्य पर कहा कि इसका मकसद कमजोर और भोले-भाले लोगों को अनुचित तरीकों से होने वाले धर्मांतरण से बचाना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, जबकि धर्मांतरण समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति को रस्म से एक महीने पहले जानकारी देनी होगी।

कंगना के पलटवार से सन्न बाबा रामदेव : जवानी पर सवाल उठाना पड़ा भारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योगगुरु बाबा रामदेव के बीच छिड़ा जुबानी जंग अब व्यक्तिगत हमलों में बदल गया है। कंगना के विवादित जनरेशन गटर बयान से शुरू हुआ यह मामला, रामदेव द्वारा उनकी जवानी और अतीत पर सवाल उठाने के बाद तीखे व्यक्तिगत पलटवार में बदल गया। कंगना के करारे जवाब से सन्न हुए रामदेव को आखिरकार यह कहना पड़ा कि वह विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल, जंतर-मंतर पर युवाओं को जनरेशन गटर कहने पर उठे विवाद के बीच, जब बाबा से कंगना के बयान पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने अभिनेत्री-सांसद पर हमला बोल दिया। रामदेव ने कहा था, 'उनका बचपन कैसा था? उनकी जवानी कैसी थी? उनके पिछले काम कैसे थे? मैं इसतरह के लोगों पर बात नहीं करना चाहता। युवाओं को जनरेशन गटर कहना विकृत मानसिकता की निशानी है।' रामदेव के इन्हीं निजी टिप्पणियों पर सांसद कंगना ने तत्काल और तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिवास्वप्न मत देखिए। अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही कुछ भी मान सकते हैं। कम से कम मुझे झूठे या भ्रामक प्रभावकारिता दावों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी।' कंगना यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने रामदेव को चरित्र पर उपदेश देने से साफ मना किया और दो टूक कहा, 'मुझे कैरेक्टर लेसन मत दीजिए। तुमसे तब बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर। नो फॉड डिटेक्टेड हियर।' यह पलटवार पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की ओर इशारा था, जहां 2024 में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी।

कोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी ने कहा- 'हमारा धर्म, हम तय करेंगे'

बोले- जज तय नहीं कर सकते कि इस्लाम में क्या जरूरी है ; फैसले को अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ बताया

हैदराबाद, एजेंसी।

स्कूलों में हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह तय करना न्यायाधीशों का काम नहीं है कि इस्लाम में कौन-सी धार्मिक प्रथा जरूरी है और कौन-सी नहीं। ओवैसी ने इसे धर्म पर हमला बताते हुए कहा, 'यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि क्या जरूरी है। जज कौन होते हैं यह तय करने वाले?'

सांसद ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों पर विचार कर रहा है। ऐसे में उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर फैसला नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ है। ओवैसी ने स्कूल छात्रा की हिजाब पहनने

की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह उसकी पसंद और निजता का मामला है। उन्होंने कहा, 'वह हिजाब अपने सिर पर पहन रही है, न कि अपने दिमाग पर।' उन्होंने दावा किया कि ऐसे फैसलों का मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम छात्राओं के स्कूल नामांकन को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि ऐसे कदम उनकी शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं।

क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल प्रयागराज के एक निजी स्कूल की छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा हाई स्कूल पास करने के बाद उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला लेना चाहती थी। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि किसी छात्र को शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह दलील भी स्वीकार नहीं की कि सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर जिन मामलों में विभिन्न हाईकोर्ट ने विचार किया है, उनमें यह राय सामने आई है कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का ऐसा अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बिना धार्मिक आस्था खतरे में पड़ जाए।

कर्नाटक : मंत्री नागेंद्र ने 89 करोड़ रुपये के कथित घोटाले पर इस्तीफे की पेशकश की

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित 89 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले के आरोपों के बीच, राज्य के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री बी.नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। विपक्षी भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) ने मामले को लेकर डीके शिवकुमार सरकार पर भारी दबाव बनाया हुआ था। विपक्षी भाजपा ने नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान लगातार विरोध प्रदर्शन किए, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क से विधानसभा का घेराव करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद विपक्ष के नेता आर. अशोक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। विपक्ष का आरोप था कि कथित घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेकर नागेंद्र को तत्काल पद से हटना चाहिए। भाजपा ने तर्क दिया कि करीब 89 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच के दौरान संबंधित मंत्री का पद पर बने रहना उचित नहीं है। लगातार विरोध प्रदर्शनों, विधानसभा में हंगामे और बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण ही नागेंद्र ने यह फैसला लिया। नागेंद्र की इस्तीफे की पेशकश को विपक्ष के निरंतर दबाव का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि, उनका इस्तीफा स्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व पर निर्भर है। विधानसभा सत्र भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन वाल्मीकि निगम के कथित घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव अभी भी जारी है।

लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी से 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर उन 20 सांसदों से जवाब मांगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सांसदों को नोटिस जारी किया और स्पीकर के पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द विचार करने को कहा है। लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत टीएमसी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उन 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है, सवाल एक तय समय-सीमा के अंदर कार्यवाही पूरी करने का है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इन 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और बाद में नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया में शामिल हो गए। अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि उनके इस आचरण के कारण संविधान के दलबदल-रोधी प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अमेरिका को की थी लीक

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी।

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को लीक की गई होगी। पूर्व सीडीएस ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर पूरी तरह द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि भारत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कैसे कर दिया।

पूर्व सीडीएस ने बताया कि गत वर्ष 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने का अहम फैसला लिया गया

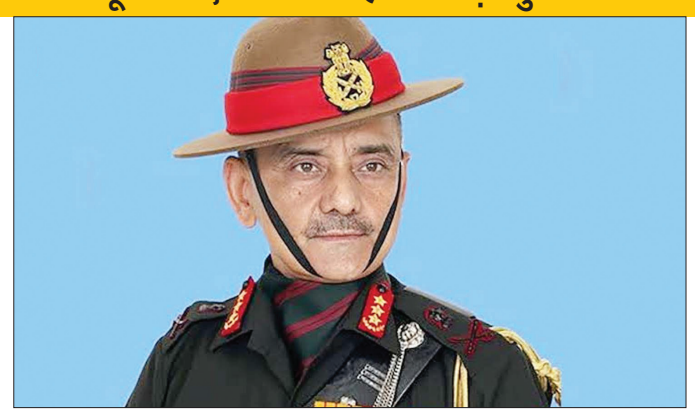

था और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेना पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। संघर्ष विराम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच आपसी सहमति से समय तय किया गया था। फोन पर बातचीत के बाद शाम पांच बजे का समय निर्धारित हुआ था, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सीजफायर केवल दो सैन्य अधिकारियों के बीच की आपसी समझ का परिणाम था। जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह गोपनीय जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सूचना भारतीय पक्ष की तरफ से बिल्कुल लीक नहीं की गई थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह जानकारी निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तान की तरफ से ही लीक हुई होगी। इसके अलावा, पूर्व सीडीएस ने किराना हिल्स पर किए गए हमलों की अटकलों पर भी विराम लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों वाले क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने समझाया कि हमलों से पहले सरगोधा क्षेत्र में कई ड्रोन भेजे गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य वहां के रडार का पता लगाना था। हवा में लंबे समय तक मंडराने के बाद यदि इन ड्रोनों को कोई लक्षित स्थान नहीं मिलता है, तो वे नीचे उतरकर टकरा जाते हैं। संभवतः इसी प्रक्रिया के दौरान कोई ड्रोन किराना पहाड़ियों से टकरा गया होगा, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने गलत तरीके से प्रचारित किया था।

5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान

सीजेपी के नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी।

जेन-जी से जुड़े एक हालिया कान्क्लेव में कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों मुख्य चेहरे अभिजीत दीपक, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल हुए। इस दौरान जब अभिजीत दीपक से सवाल किया गया कि क्या वे दिल्ली केवल बवाल मचाने आते हैं और उन्होंने फिर से मार्च का ऐलान क्यों किया है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाना है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है।

दीपके ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के लिए एक करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि सांसद और विधायकों की खरीद-फरोख्त में 50 से 100 करोड़ रुपये आसानी से खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की मदद करने में कंजूसी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी प्रमुख मांग छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत वापस लेने की है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने शिक्षा से जुड़े अधिकार मांग रहे थे, न कि किसी से वोट। कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए दीपके ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को इंडिया गेट 1.0

के तहत वे इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक शांति मार्च निकालेंगे। उन्होंने बताया कि वे आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से मिले थे, जिनके पिता को बेटी की मौत के सदमे में पैरालिसिस और हार्ट अटैक आ गया था। उस परिवार ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था और अब वे गहरे आर्थिक संकट में हैं। चर्चा के दौरान आशुतोष रांका से जयपुर में हुई घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे वोट मांगने नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। राजस्थान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी यदि राजधानी के पास स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहे हैं, तो यह शर्मनाक है। हिंसा के डर से जुड़े सवाल पर अभिजीत दीपक ने तंज कसते हुए कहा कि वे और रांका पहले ही पुलिस या विरोध के दौरान पिट चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वे आगे भी प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार हैं। सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के रवैये पर बात करते हुए कहा कि मंत्रियों के वादों के बावजूद युवाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर की सूची मांगने और केंद्र सरकार के वकीलों द्वारा इस पर स्पष्ट प्रतिबद्धता न दिखाने के कारण उन्हें युवाओं के हित में यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है।

जनता ने जिस सीएम को नकारा है उन्हें वही पसंद है : पूनावाला

-शहजाद का अभिजीत दीपके पर पलटवार

नई दिल्ली, एजेंसी।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा कुछ मुख्यमंत्रियों को देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं की सूची में शामिल करने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे शहजाद पूनावाला ने अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पर तीखा हमला बोला है। पूनावाला ने कहा है कि दीपके को जिन मुख्यमंत्रियों को अच्छे लगते हैं, उन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने सीजेपी को फ्रॉड पार्टी करार देते हुए दीपके के चुने गए तीन मुख्यमंत्रियों के चयन पर गंभीर सवाल उठाए।

हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिजीत दीपके ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) के नेता एमके स्टालिन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में शामिल किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें

उनकी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सीजेपी को वो सीएम अच्छे लगते हैं, जिन्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने तंज कसा कि कॉकरोच जनता पार्टी में से जनता को हटाकर सिर्फ कॉकरोच पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जनता का निर्णय कुछ और रहा है। पूनावाला ने अभिजीत दीपके के दावों का खंडन करते हुए तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर एमके स्टालिन के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन ने तमिलनाडु की नहीं, बल्कि अपने परिवार की अर्थव्यवस्था और अपने बेटे का उदय किया। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि स्टालिन के पांच सालों के कार्यकाल में तमिलनाडु का कर्ज 2021 में 4.86 लाख करोड़ से बढ़कर 9.52 लाख करोड़ हो गया था। पूनावाला ने टिप्पणी की, जितना 60-70 सालों में बढ़ा, उतना पांच सालों में स्टालिन ने बढ़ाया। ये अच्छा कर रहे थे इकोनॉमी को।

केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ पर भी पूनावाला ने आपत्ति जताई। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि केरल की आबादी साढ़े तीन करोड़ थी, और आंकड़ों के अनुसार वहां 71 हजार मौतें हुईं। इसकी तुलना में, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ थी और वहां कोविड से जुड़ी मौतें 23 हजार 700 हुईं थीं। पूनावाला ने इसे कुप्रबंधन बताते हुए कहा, छोटा राज्य होने के बावजूद केरल में यूपी से ज्यादा मौतें हुईं। ये था केरल हेल्थ मॉडल।

अन्नपूर्णा योजना पर ममता के सवाल, सुवेंदु ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह अन्नपूर्णा योजना को लेकर उठे सवाल हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर योजना के लाभ को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए उनके आरोपों का जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

ममता बनर्जी ने सोमवार दोपहर सोशल मीडिया लाइव के दौरान अन्नपूर्णा योजना को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और आरोप लगाया कि लाभार्थियों के चयन में जाति को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने की अपील की, जिन्हें कथित तौर पर योजना का लाभ नहीं मिला है। ममता ने कहा कि वह लोगों के साथ पहले भी खड़ी थीं और आगे भी रहेंगी।

सुवेंदु ने बताए लाभार्थियों के आंकड़े

ममता के आरोपों पर सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 45 लाख 64 हजार 472 लाभार्थियों को फायदा मिला है। उनके मुताबिक, इनमें करीब 19 लाख 20 हजार मुस्लिम लाभार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि योजना का लाभ देते समय जाति और धर्म को आधार नहीं बनाया जाता।उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की करीब एक लाख महिलाओं को योजना के तहत लाभ मिलने का भी दावा किया। नंदीग्राम के एक ब्लॉक का उदाहरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि वहां दो हिंदू और 52 मुस्लिम परिवारों को आवास के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उनके मुताबिक, सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले।

सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा योजना को लेकर सरकार के पास करीब 4.5 लाख शिकायतें पहुंची हैं। इनमें योजना का लाभ मिलने और लाभ से वंचित रहने, दोनों तरह की शिकायतें शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि योजना का उद्देश्य सभी पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना था तो शुरुआत में इसे 25 से 60 वर्ष की आयु सीमा तक क्यों सीमित किया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। आंकड़े गिनाने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया लाइव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता दोपहर में सोशल मीडिया पर ही रहती हैं और उन्हें सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं है।उन्होंने ममता की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर भी कटाक्ष किया और बारुईपुर तथा हलीशहर में उनके कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए खेल के उदाहरण दिए।